THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Dr. B. B. Dutta-abcent. Shri Murli Manohar Joshi.

डा० **मुरली मनोहर जोशी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं श्री कृष्ण लाल शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह विधेयक सदन के सामने विचारार्थ रखा है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश बेहोशी में है और जब कभी ऐसे विधेयक आते हैं तब मैं यह मानता हूं कि देश को बेहोशी में (व्यवधान)

ANNOUNCEMENT REGARDING WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM EGYPT

THE VICE-CHAIRMAN (KUMARI SAROJ KHAPARDE): Hon. Members, I have an anouncement to make. We have with us, seated in the Special Box, Members of the Parliamentary Delegation from Egypt, currently on a visit to our country, under the distinguished leadership of His Excellency, Dr. Ahmed Fathi Sorour, Speaker of the People's Assembly of Egypt. I, on my own behalf and on behalf of the Members of the House take pleasure in extending a hearty welcome to the leader and other Members of the Delegation and wish that our distinguished guests will have an enjoyable and fruitful stay in the country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Parliamentary system, our country and our people and their visit to this country will further strengthen the friendly bond that exists between India and Egypt. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Members of the People's Assembly and the friendly people of Egypt. Thank you.

THE PREVENTION OF INFLUX OF FOREIGN NATIONALS IN THE COUNTRY BILL, 1991--contd.

डा० **मुरली मनोहर जोशी** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और श्री कृष्ण लाल शर्मा जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत उचित समय पर इस विधेयक के द्वारा सरकार का और देश का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की है और देश को बेहोशी से जगाने की चेष्टा की है। पिछले दिनों इस देश में जिस तरह से घुसपैठ बढ़ी है, इनफिल्ट्रेशन बढ़ा है उससे सारे देश को चिंता हो रही है। बंगला देश से जो घुसपैठ हुई है उसका अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है कि वह कितनी ज्यादा संख्या में हुई है। देशों की जनगणना की तुलना से, बंगला देश और भारत की 1991 की जनगणना की तुलना से इसका अंदाज लग सकता है। बंगला देश की 1991 में अनुमानित जनसंख्या 10 करोड़ 48 लाख और वार्षिक वृद्धि दर 2.02 प्रतिशत थी, जबकि 1981 में यह दर 3.13 प्रतिशत रही थी। बंगला देश की सरकार ने पहले 1991 की जनसंख्या का अनुमान लगभग 11 करोड़ 40 लाख लगाया था, यू०एन०डी०पी० का अनुमान 11 करोड़ 60 लाख 1990 में था और 11 करोड़ 60 लाख 1991 में था। और 11 करोड़ 80 लाख 1991 में था। इस प्रकार बंगला देश की सरकार के अनुमान से लगभग 90 लाख जनसंख्या 1991 में कम रही, जबकि यू०एन० डी०पी० के अनुमान से लगभग एक करोड़ कम रही। सवाल उठता है कि यह एक करोड़ लोग कहां चले गए? बंगाल की खाड़ी में, बर्मा में, अराकान में या हिन्दुस्तान में। मैं सिद्ध करना चाहूंगा कि यह एक करोड़ लोग बंगला देश से हिन्दुस्तान आए। जनगणना के अन्य आंकड़ों से यह भी प्रतीत होगा कि 70 लाख कम से कम और एक करोड़ 20 लाख के लगभग इन 10 वर्षों में 1981 से 1991 तक बंगला देश के लोग यहां आए। त्रिपुरा से हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं। उनको मालूम

[श्री मुरली मनोहर जोशी]

है कि कितनी बड़ी संख्या में त्रिपुरा में बंगला देश की घुसपैठ हुई है। पश्चिम बंगाल में भी जनसंख्या की वृद्धि दर देश की सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा है। यहां तक कि जो घोषित वृद्धि दर पाकिस्तान की है, उससे भी अधिक है। स्मरणीय है कि बंगला देश सबसे अधिक दर से जनसंख्या में वृद्धि करता है। एक बात और भी देखी जा सकती है कि बंगला देश से सटे हुए जो पश्चिम बंगाल के जिले हैं, उनमें जनसंख्या वृद्धि की दर औरों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका भी उल्लेख मैं करूंगा। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में 3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जब कि उससे सटे बांगलादेश के राजशाही जिले में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका अर्थ ये है कि यहां वृद्धि ज्यादा होनी चाहिए थी, वहां वृद्धि कम हुई और जहां कम होनी चाहिए थी, वहां वृद्धि ज्यादा हुई। तो ये अंतर क्यों है? दोनों जिले सटे हुए हैं लेकिन राजशाही से मालदा और मुर्शिदाबाद में अभि निष्क्रमण जारी है।

इसी तरह भारत के नदिया जिले में 3 प्रतिशत की वृद्धि, बंगला देश के पुष्तिया जिले की 2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में हुई है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, जिससे जाहिर होगा कि यह समस्या कितनी बड़ी है और कितनी विशाल है। आसाम में ग्वालपाड़ा जिले में 1951–61 के दशक में 34.32 की दर थी जनसंख्या वृद्धि की, जो 1961–71 में बढ़कर 44.12 हो गई। कामरूप में 38.39 थी, उतनी ही रही। दारंग में 39.64 रही। नौगांग में 36.51 से बढ़कर 38.83 रही। डिब्रुगढ़ में घट गई। लखीमपुर में 52.8 से बढ़कर 58.56 हो गई। शिवसागर में 24.4 थी, उतनी ही रही। नार्थ कचार हिल्स में 36.95 से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई।

यह तो रहा 1971 तक लेकिन 1971 के बाद जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वह तो बेतहाशा है। वृद्धि इस तरह से है कि जो इलेक्टोरल रोल्स की गणना की गई 1952 और 1966 में, उसकी तुलना में 1989 की इलेक्टोरल रोल्स की सूची में सिर्फ 79 परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए थी लेकिन यह वृद्धि, अगर 18 से 30 साल तक की उम्र के लोगों को निकाल दिया जाए, जो कि नेचुरल है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उनकी वृद्धि को तो मैं मानता हूं कि नागरिकों की वृद्धि है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो यह वृद्धि बिल्कुल माईड-बौगलिंग है। महोदया, 8.2 लाख वोटर 1989 की वोटर लिस्ट में ज्यादा है, जो कि नहीं होने चाहिए थे, अगर सामान्य वृद्धि की दर आसाम में रहती। यह सरकारी आंकड़े हैं। कांस्टीट्यूऐंसीज का सर्वे कराया होम-मिनिस्ट्री ने, वह तो और भी खतरनाक है। महोदया, 14 ऐसी हैं जिनमें वोटर्स का प्रतिशत 100 से 150 प्रतिशत तक बढ़ा है। इसी तरह 16 ऐसी हैं जिसमें 90 से 99 परसेंट बढ़ा है, 13 में 80 से 89 परसेंट तक बढ़ा है, 16 ऐसी हैं जिसमें 70 से 79 परसेंट तक बढ़ा है, 15 ऐसी हैं जिसमें 60 से 69 परसेंट तक बढ़ा है और ये 18 से 21 साल तक के लोगों को निकालकर है। महोदया, 14 ऐसी हैं जहां 50 से 59 परसेंट तक बढ़ा है, 13 ऐसी हैं जहां 26 से 49 परसेंट तक बढ़ा हैं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर आवश्यकता पड़े तो इन कांस्टीट्यूऐंसीज का नाम अपने यहां देख लें, आपके यहां उपलब्ध है।

इस तरह से आप देखेंगे कि आसाम के अंदर भारी मात्रा में वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई और पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, बंगला देश से आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और साथ ही साथ वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई। अब आप जरा देखिए कि इरादे क्या हैं अभी कोई मित्र कह रहे थे कि कहीं-कहीं दिक्कत होती है और हमारा देश बहुत अच्छा है, सुंदर है, यह तो मैंने माना, इसके लिए हम परमात्मा के बहुत ऋणी हैं कि हमें इतना सुंदर देश दिया लेकिन उसकी सजा हमें क्यों

मिले? मैं आपके सामने मिस्टर सादिक खान, जो हालीडे ढाका में एक वोकली में उनका एक लेख छपा है अक्टूबर 18, 1991 में जिसका टाइटिल है–

"The Question of Lebensraum",

के उस लेख की कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पर ध्यान दें गृह मंत्री जी कि बांगलादेश के इरादे क्या हैं।

"The question of *lebensraum* or living space for the people of Bangladesh has not yet been raised as a moot issue. All projections, however, clearly indicate that by the next decade, that is to say by the first decade of the 21st century, Bangladesh will face a serious crisis of *lebensraum*. No possible performance of population planning, actual or hypothetical, significantly alters that prediction".

वह कहते हैं कि बांगलादेश अब गरीब हो गए हैं।

"Will Bangladesh as a small nation-State be able to shoulder this problem alone? The plain answer is no, and Bangladesh need not be ashamed on that account either. The battle for dominion of the seas in the Bay and the impositions of zones of piracy and power in the estuaries by Western maritime intruders in the sixteenth and seventeenth centuries culminating in the colonial devastation of Bengal in the eighteenth and nineteenth centuries left the region of Bangladesh bereft of the traditional strength of technology and productivity."

हिन्दुस्तान की गरीबी का कारण भी कालौनियल पावर्स द्वारा की गई लूट है। हम उन से दूर नहीं हैं।....

Because of the misdeeds of colonial powers, Bangladesh has ben reduced to penury. So is India.

इसलिए वहां जब आबादी बढ़ाई जा रही है। एक आदमी के एक परिवार में बढ़ने का मतलब है कि वह आमदनी का जरिया बन जाएगा। इस लिए वह कहते हैं–

"It was largely reduced to the level of a survival agricultural economy in which an extra hand of an offspring became an asset. Religious bias aside, the culture of poverty, historically devolved from colonial differentiation and neglect, is an infection inducing population explosion that the country take a long time yet to be connect of. The predicament of Bangladesh is not entirely of its own making. In the professed new world order, therefore, there should not be any hesitation on the part of Bangladesh to seek equitable sharing of responsibility from the developed world to sort out its problem of overpopulation and lebensraum."

मुझे बड़ी खुशी होती अगर यह सवाल बंगला देश उठाता कि उसकी बढ़ती जनसंख्या को आस्ट्रेलिया में, साइबेरिया में भेज देते, वहां बहुत भमि है तो हम भी उस की मदद करने को तैयार होते। अब ध्यान से सुनिए–

"We shall hope for the best in international co-operation. We shall hope for the best in accommodation from the developed world. In reality, nevertheless, Bangladesh may expect little external relief in the short run on the issue of lebensraum. It is also doubtful that Bangladesh may develop sufficient sustainable urbanisation or can engineer sufficient reclamation of habitable land from its own off-shore potential to settle its projected population growth in the next decade. A natural overflow of population pressure is, therefore, very much on the cards and will not be restrainable by barbed wire or border patrol measures. The natural trend of population overflow from Bangladesh is towards the sparsely populated lands of the south-east in the Arakan side and of the north-east in the seven sisters side of the Indian sub-continent."

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

हमें लिविंग स्पेस चाहिए। सेवन सिस्टर्स में चाहिए। त्रिपुरा में तो वे आ ही गए हैं। मंत्री जी आप यहां पर बैठे हुए हैं। बचाइए देश को। हम चाहते हैं कि आप इस बिल का समर्थन करें। मैं बताऊंगा त्रिपुरा में क्या हालत है। यह एक लंबा लेख है।

एक और दूसरा लेख है जो कि न्यूजपेपर मार्निंग सन में 4 अगस्त, 1991 को छपा था।

In a Dhaka newspaper, *The Morning Sun*, dated August 4, 1991 under the caption "One Crore People Missing", it is stated:

"Some one crore people are missing from the country, according to the figures contained in the preliminary report of the 1991 census and the official population data used so far.

The preliminary census report, published recently, said that the population stood at 10.80 crore while the official figure in use till recently was 11.75 crore.

Experts wonder which of the figures is correct."

Both the figures are correct. One is the amount of population which grew there and the other is which was retained and the balance which had been transferred to this country very safely.

यह परिस्थिति है जिस की तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान)

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): This provision or estimate, which you gave, if it was undertaken by the census authorities there, it means that these people were there at that time when the census was undertaken. This means in one year the population has grown by one crore.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: This was the estimate. This was the projected estimate for the decade.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Then it cannot be the actual count.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The actual count was less. That is why it was the projected figure. I can give a number of districts in Bangladesh where the population exactly tallies with the projected growth (*Interruptions*).. I can tell you the district in Bangladesh where the amount of population is less by the same amount by which there is an increase in Assam and Bengal. That is the case. Dr. Biplab Dasgupta, please bear with me. You are responsible. Your Government in Bengal is responsible for all these things and the Congress Government in Assam is responsible for this holocaust in Assam and in Tripura.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): We should also discuss your memorandum to the Election Commission. (*Interruptions*). Why are you worried? He has mentioned my name.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am neither using the words 'Hindu' nor 'Muslim'. I am talking about infiltration from Bangladesh.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: I am mentioning about your memorandum to the Election Commission of India which was signed by your party.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: That is a separate issue. Please bear with me. I will tell you how you have been responsible for destroying Tripura. The first and foremost evidence is an all important document—a brochure entitled, Influx—Infiltration from East Pakistan, produced by the Directorate of Advertising and visual Publicty, Ministry of Information and Broadcasting for the Ministry of

External Affairs, Government of India and printed by Albion Press, New Delhi, published in August, 1963. Relevant portion is reproduced below:

'...Long before the cry of partition was heard in United India, the low but steady encroachment of Assam and Tripura by immigrants from areas now in East Pakistan was already in progress. Partition came and new international frontiers were written across India.'

'....The new frontier between East Pakistan and India ran along 2500 miles of largely flat territory. It was, and remains till today, an open frontier.

....Partition did not assuage the land hunger in East Pakistan. The new international boundary was not physically marked on the ground and was largely unguarded and virtually unpetrolled".

Then it says:

"There is sufficient foolproof evidence to show that land-hungry immigrants from Pakistan speaked through the border, dispossessed innocent tribesmen of their forests and lands, cultivated these and even paid land revenue until their ownership of the land was discovered to be fraudulent. Through these questionable means, with occasional connivance of petty local officers, some of the illegal immigrants armed themselves with dubious documents of registration of property. A great majority of illegal immigrants encroached and took over the Government land.

It is interesting to examine the growth of population in East Pakistan, districtwise, during 1951-61..."

Now, I will give you the percentage growth. The percentage of growth in 1951-61 was like this: Chittagong Hill Tract—34.0, Kustia— 31.5, Rangpur—29.0, Jessore—28.7, Chittagong—28.6, Rajshahi—27.1, Dacca—24.8, Dinajpur—24.0, Pabna—23.3, Bogra—22.8, Mymensingh—21.0, Khulna— 17.8, Faridpur—16.9, Bakarganj —16.8, Commilla—15.4, Sylhet—13.9 and Noakhali—4.7.

बिल्कुल एक समान वृद्धि दर है कुछ इलाकों में। जहां घटा है वे कौन से इलाके हैं वे भी मैंने बताये। जहां से बांगलादेशी ट्रांसफर हुए हैं वे हैं खुलना 17 परसेंट, फरीद पुर 16 9 परसेंट, बकरगंज 16.8 परसेंट, कोमिला 15.4% सिलहट 13.9 परसेंट, नौआखली 4.7 परसेंट। यह 51 से 61 तक की श्रोव है।

It again says:

"Every natural consideration would argue in favour of a reasonably uniform rate of growth of population of the entire East Pakistan. The sharp trough and crests in the rate of population growth in the different East Pakistan districts only mean that there was out migration from the districts with appreciably low rates of increase. It is precisely from the districts of Bogra, Mymensingh, Khulna, Faridpur, Bakarganj Commilla, Sylhet and Noakhali, that the great majority of illegal immigrants have infiltrated into Assam, West Bengal and Tripura.'

This is what the Government of India said in 1963.

पर यह आज वैसा नहीं कह रहे हैं।

Naturally one would like to know whether the Government acted after so much of definite knowledge about illegal infiltration became available.

क्या किया आपने ? 63 से 94 तक 31 साल हो गये आपने इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं है। यह निरन्तर बढ़ता चला गया। आगे इसी डाकुमेंट में लिखा है:

"There has been only one instance of large scale deportation till now. This was in Tripura in May/June, 1963, when about 3,000 aliens, in

[Shri Murli Manohar Joshi]

all, were asked to leave the Union Territory. There have been no large scale deportations or evictions from Assam or West Bengal. It makes necessity of a protest imperative and long overdue. The potentiality of the threat to the sovereignty of our country was fully revealed by the same document."

अब और सुनिये डाक्यमेंट क्या कहता है।

"The fact is that enlistment of foreigners in the voters' list has at times taken place at the instance of politically interested persons or parties. Political parties have been known to take dubious steps to inflate the numbar of their supporters at the election time, and some undoubtedly used the illegal settlers from Pakistan towards this end."

मैं समझता हूं कि देश को शर्म आनी चाहिये इस बात पर, उन पोलिटिकल पार्टीज के कंडक्ट पर जिन्होंने पाकिस्तान के नागरिकों को इस देश की वोटर लिस्ट में शामिल करवाया, इस देश में सेत्ता हासिल करने के लिये। इससे ज्यादा इस देश के लिये दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है।

"A person's name, rightly or wrongly, inscribed in the voters' list does not prove or confer Indian nationality or citizenship. This legal position has been confirmed by decisions of the Supreme Court of India. Many Pakistani nationals who left Tripura themselves stated on return that they had helped worked and voted for the candidates of a particular political party of India."

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह यह पता लगाकर बतायें कि वे पोलिटिकल पार्टीज कौन थी? उनकी थी या सीपी०एम० की थी यह बता करके बतायें। यह डाक्युमेंट कहता है कि :

"These foreigners were no doubts assisted through questionable practices to have their names on the voters' list."

इसलिये आप उनके नाम वोटर लिस्ट से कटवायें। क्या यह जरूरी नहीं होगा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किये जायें। सन 63 में डूबियस तरीके से जिनका नाम लिखा गया था, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि किस तरह से इस देश में जनतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, किस तरह से सत्ता में बने रहने के लिये विदेशी नागरिकों का प्रयोग किया जा रहा है। देश के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया जा रहा है, इतनी बड़ी बिडंबना इतने बड़ देश के ऊपर क्यों लादी जा रही है, देश के ऊपर क्यों यह अभिशाप लादा जा रहा है? मैं समझता हूं कि शायद आपके लिये यह ठीक भी है क्योंकि जिस तरह से आप हर चीज इम्पोट करते हैं, पैसा इम्पोर्ट करते हैं, टेक्नालाजी इम्पोर्ट करते हैं उसी तरह सत्ता में रहने के लिये वोटस की इम्पोर्ट करना चाहते हैं।

"The effort of the aliens has been to accumulate circumstantial evidence since they lacked primary and essential proof of Indian Nationality." This was the assessment of the problem of infiltration by the Government of India in 1968."

आपके अपने जनरल सेक्रटरीज की रिपोट है, कांग्रस वालों की।

the Report of the General Secretaries (1st March to 2nd July, 1989) to the Seventh General Conference of the North-Eastern Congress (I) Co-ordination Committee—Guwahati, 3rd July, 1992.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): They are not the General Secretaries. They must be leaders from the North-East.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: They are the General Secretaries of the North-Eastern Council.

जिस पर हस्ताक्षर हैं आर०सी० चिते जमीर, डी०डी०पुच, एच०के० बोरा, बी०बी० दत्ता एवं लिएन सुआमा के। I will read some part of it.

"In 1972, there were 7.5 lakh Bihari Muslims in the camps in Dacca. As a result of mediation by Saudi Arabia, 33,000 of them only were accepted by Pakistan. At present, there are less than two lakhs in the compas. Where have the rest gone?" They have also gone back. "Bangladeshi journalists met Bangladeshi Muslim families residing in Delhi, took their pictures and wrote about their life-style in a Dacca daily. According to them, there are about 1.5 lakh Bangladeshi Muslims in Delhi. According to other sources, the number will be more than 3.5 lakhs." Your own report says that. "Whatever be the number, they came from Bangladesh. In July, 1990, the Bangladeshi Muslims residing in West Bengal formed an organisation named 'Bangladesh Mohajir Sangathan." They are also registered.

उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस की उन्होंने डिमांड की कि हम हिन्दुस्तान में रहेंगे, यहां की नागरिकता लेंगे और हिन्दुस्तान से बाहर नहीं जायेंगे। यह राइटर्स बिल्डिंग के ठीक सामने हुआ। मैं ज्योति बसु को... (**व्यवधान**)...प्रैस कान्फ्रेंस हुई, प्रैस क्लब में, उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास है। मैं यह पूरी रिपोर्ट पढ़ सकता हूं कि इसमें उन्होंने क्या क्या डिमांड की। उन्होंने कहा कि एक लाख हम यहां मौजूद हैं और एक लाख और हमारे लोग हैं। हमारी पांच लाख की मेंबरशिप है। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी इन्फिलटेटर्स की है जो खुले आम कहती है कि हमने वीसा नहीं लिया है और हम इस देश में घुसपैठ करके आये हैं। हम यहां रहेंगे, खायेंगे और हम इस देश को बरबाद करके छोड़ेंगे और मंत्री महोदय आप यहां चुप होकर बैठ हैं। कल साहब सुबह थे, इस वक्त नहीं हैं।

"Shri M. M. Jacob, Union Minister of State for Home Affairs, said in Parliament in December, 1991, in reply to a question, that there were one lakh Bangladeshi nationals in Delhi and 5.87 lakh in West Bengal."

4.00 PM.

यह तो आपके रिकार्ड है, जो आप कह रहे हैं। लेकिन स्थिति इससे कहीं बहुत ज्यादा..(**समय की घंटी**) महोदया, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं थोड़ा समय और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपने 3 35 पर स्टार्ट किया था जोशी जी।

डा० मुरली मनोहर जोशी: बीच में मुझे डिस्टब भी किया गया। आगे क्या कहते हैं। (**व्यवधान**)

Here, we are speaking from records.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): मैं इनको अपना समय देने के लिए तैयार हूं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: आगे क्या कहते हैं—

"It would be interesting to note that a group of intellectuals in Dacca is seeking to legitimise the migration of Muslims...by invoking the theory of *lebensraum* or living space. A number of Dacca dailies carried articles written on these lines..."

"From the above we may infer: There are infiltrations—though it is a difficult task to examine the precise number. The infiltrations are not only by minorities of Bangladesh but also from the majority community Muslims. In absolute terms, the number of Muslims crossing into India is likely to be much larger than that of non-Muslims. An ideological suport is given to the phenomenón by the Islamic fundamentalists creating the vision of a larger Islamic country comprising Bangladesh and the entire

[Shri Murli Manohar Joshi]

North-East where its economic problems will be solved and security ensured. There is a direct correlation between the rise of fundamentalism and increase in influx."

आप इसकी पूरी रिपोर्ट मंगा कर देख लें, आपके पास होगी। यह रिपोर्ट बड़ा भयानक चित्र प्रस्तुत करती है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैंने श्री रघुनन्दन लाल भाटिया को यह रिपोर्ट दे दी है (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): राजेश जी को भी दे दीजिये।

श्री राजेश पायलट। मैं मंगा लूंगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी: अब पश्चिमी बंगाल के पूर्व गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या है। मैं यह भी आपको पढ़ कर के सुना दूं।

"Demographic Aggression Against India—Muslim Avalanche from Bangladesh" by Baljit Rai, a retired Director-General of Police.

उनकी यह लिखी हुई पुस्तक है जो 1993 में छपी है। इसमें उनकी रिपोर्ट है।

"Report No. 1 (STATESMAN. April 6 and 8, 1990)—

Serious Influx from Bangladesh—

"Shri T.V. Rajeshwar, former Governor of West Bengal highlighted the problem of infilteration of Muslims from Bangladesh in two-part article. Relevant portions of the article are reproduced below:

'The basket-case of Asia, as Henry Kissinger described Bangladesh, pours out in thousands its teeming millions all over the subcontinent not to speak of West Asia and elsewhere abroad. They have sneaked into the remotest parts of Arunachal Pradesh..."

And here, I am also to tell you that in Sikkim, 40 per cent of the labour force is now Bangladeshi.

अगर उनको वोटिंग राइट मिल गया तो कुल मिला कर उनकी सिक्किम की कहीं जनसंख्या से ज्यादा है फिर नर बहादुर भंडारी भी नहीं रहेंगे और जिसको आप चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं वह भी नहीं रहेंगे। कोई बंगलादेशी ही रहेगा।

SHR RAJESH PILOT: I am sorry. This is wrong. We do not want to make anybody Chief Minister in Sikkim. We have not got anyone. Let it be very clear.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: It further says:

"The Bangladeshis have been spread out all over India. In Punjab and Haryana they are indispensable as farm labour during the harvest season. They are used as expendable couriers both by the Punjab terrorists and Pakistan Rangers.

There is a Bangladeshi colony in trans-Jamuna area in Delhi.

However, it is in the neighbouring States of Assam, Tripura, West Bengal and Bihar that the impact of Bangladeshi immigration is overwhelming. In Tripura, the demographic picture has undergone a total change after partition.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): जोशी जी से मेरा आग्रह है कि सब रिपोर्ट हम लोगों को दे दें लेकिन आप अपना मंतव्य तो बताएं। (**व्यवधान**)

डा० मुरली मनोहर जोशी: खुद का मैं बता रहा हूं। आप परेशान क्यों हैं पचौरी जी।

श्री सुरेश पचौरी: इनका खुद का मंतव्य क्या है। (**व्यवधान**)

SHRI MD. SALIM (West Bengal): The whole book should be laid on the Table.

डा० मुरली मनोहर जोशी: मैं अपना मंतव्य बता रहा हूं। अपने मंतव्य के समर्थन में मैं यह चाहता हूं कि आप जैसे लोग मेरे साथ जरा चलें उनको बाहर करने आएं **(व्यवधान)** अगर मैं यह कहे दूं कि मेरा मंतव्य यह है तो आप मुझे कम्यूनल कहेंगे **(व्यवधान)**

श्री सुरेश पचौरी: पड़ रहेंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी: आप पढ़ेंगे नहीं, सुनने के लिए आए हैं।

श्री पचौरी: आधा घंटा हो गया है। **व्यवधान))**

डा; मुरली मनोहर जोशी: आपको तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण लाल शर्मा: जब मैं बोल रहा था तब आप कह रहे थे कि क्यों बोल रहे हैं **(व्यवधान))**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): जोशी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने 3.35 पर शुरू किया है। अगर संक्षेप में बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी: अगर मेरे मित्र डिस्टर्ब नहीं करें तो मैं संक्षेप में कहूंगा वरना मैं इतना विस्तार करूंगा कि आपको पता चल जाएगा.. (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप थोड़ा संक्षेप में कहें।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

"As per the 1981 census, while the Muslim population in West Bengal constituted 21.51 per cent, it accounted for a percentage ranging from 31 in Birbhum district to 58.66 in Murshidabad district. The districts of West Dinajpur, Malda, and the North and South 24 Parganas accounted for figures ranging bttween these two percentage. What the current figures are cannot be said with any accuracy but it can be safely assumed that a serious demographic change has taken place in these districts largely due to continuous influx of Bangladeshi migrants..."

यह गवर्नर साहब कह रहे हैं, जो पश्चिमी बंगाल में गवर्नर रह चुके हैं। उनका कहना है। डाइरेक्टर इंटेलीजेंस भी रहे हैं। यह उनकी रिपोर्ट है। अभी प्रकाश सिंह जी, जो डाइरेक्टर जनरल आफ बी.एस.एफ. रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर उत्तर-पूर्वांचल में और इन सारे बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स में स्थिति को संभाला नहीं गया तो काश्मीर से ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इनफिल्ट्रेशन जबदस्त है। मैं पिछले दिनों त्रिपुरा गया था चुनाव की सभाओं के दौरान अगरतला में जहां मेरा मंच बना हुआ था अगरतला के गांव में, वहां जितनी मेरे मंच के आगे भीड़ थी उतनी ही पीछे भीड़ थी। लेकिन लाउड स्पीकर सब मंच के सामने लगे हुए थे। मैंने लोगों से पूछा कि यह भीड़ पीछे है आपने लाउड स्पीकर क्यों नहीं लगाए। कहने लगे कि वह तो बंगलादेश है। वहां से लोग सुनने आते हैं जब यहां कोई पोलिटीकल पार्टी की मीटिंग होती है। मैंने कहा कि यहां कोई डिमारकेशन नहीं है। कहने लगे कि डिमारकेशन का कोई सवाल ही नहीं है। ये लोग आते हैं और चले जाते हैं। मुझे एक डाक्टर ने वहां यह बताया कि इनफिल्ट्रेशन का एक बहुत ही नया तरीका ढूंढा गया है। बंगलादेश से गर्भवती महिलायें भारत में आती हैं, क्योंकि रास्ता खुला हुआ है, कोई रोक-टोक नहीं है किसी तरह से सामान्य तौर पर उनके जीवन में रहन-सहन में कोई फर्क नहीं है। वे यहां के अस्पतालों में आकर प्रसव करते हैं और बच्चा भारत का नागरिक बन जाता है। उसको नागरिकता का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसको अपने साथ वापस भी ले जाती हैं। साल भर, दो साल, तीन साल का होने के बाद उसको हिन्दुस्तान में अपने किसी रिश्तेदार के यहां लाकर रख देती हैं। इसको चक करने का आपके पास क्या जरिए हैं? यह कहा जाता है

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

कि सिर्फ गरीबी से ऊब करके यहां लोग आ रहे हैं और बडी मानवता की बात कही जाती है। मैं बंगलादेश की मानवता के नाम पर मदद करने के लिए तैयार हू। हजार, दो हजार करोड़ रुपया अगर हमें अपने प्लान में से उनको मदद करने के लिए देना पड़े, हम देंगे। लेकिन आज जो यह दो करोड़ लोग इस देश में बैठे हुए हैं और पांच रुपया प्रति व्यक्ति भी अगर इस देश में प्रतिदिन खर्च करते हैं तो दस करोड रुपया प्रति दिन खच करके और इस तरह से साल भर में लगभग चार हजार करोड़ रुपए का बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा। 6 हजार करोड़ रुपया आपके बजट का घाटा है। इसलिए अच्छा यह है कि हम बगलादेश की मदद कर दें। हम उनको एक हजार करोड़ रुपया सीधे ही दे कि तुम कुछ अपने यहां विकास करो, आर्थिक विकास करो जनसख्या नियन्त्रण के कार्यक्रम लो, लेकिन हमारे यहां भगवान के वास्ते इस इन-फिल्ट्रेशन को, इस इनफ्लक्स को न भेजें। मैं आपसे कहना चाहता हू गृह मन्त्री जी मामला बहुत संगीन है, बहुत गभीर है। बार-बार घटी जा रही है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इसके कितने डाइमेंशन हैं। पिछले दिनों श्री विष्णु पांडेया ने गुजरात की एक रिपोर्ट प्रकाशित की कच्छ के रण में एक बंगलादेशी तस्करी करते हुए पकड़ा गया। आपकी पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने जवाब दिया मैं तो ढाका से आया हू। पूछा कि ढाका से कच्छ के रण में किस रास्ते से आए, समुद्र के रास्ते या जमीन के रास्ते? कहने लगा, मैं ढाका से कल-कत्ता आया। किसी ने रोका ही नहीं। कलकत्ता से मैं दिल्ली तक चला आया। कोई मुझसे बोला ही नहीं। दिल्ली से मैं अमृतसर चला गया। किसी ने टोका ही नहीं। अमृतसर से फिर लाहौर और तस्करों के साथ वहां से कच्छे के रण में। तो आपने देश को धर्मशाला बना दिया है। इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर चले आओ। यह बिल इस बात की रोकथाम करना चाहता है। मैं चाहूगा कि आप इस देश में नागरिकता का रजिस्टर लागू करें। उसे क्यों नहीं लागू किया जाता? रजिस्टर आफ नेशनल्ज भारत के राष्ट्रीय लोगों का एक रजिस्टर बनना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसमें उसका नाम दज होना चाहिए और उसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए वह चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, नागरिकता की पहचान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूण होगा और इसमें खच का कोई ख्याल नहीं किया जाना चाहिए। आप करोड़ों रुपए खच कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं काश्मीर की घाटी में। अगर वहां फोटो आइडेंटिटी कार्ड पहले से होते तो आपको मुजाहिद्दीन को पकड़ने के लिए बहुत मदद मिलती, उनको छांटने के लिए और उनको देखने के लिए। इसी तरह से मैं आपसे चाहूगा कि आप जल्दी से जल्दी उस तरीके को इजाद करें, उस मैकेनिज्म को बनाएं जिससे कि बगलादेश से आए हुए घुसपैठियों, पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों का अभिज्ञान किया जा सके, आइडेंटिटी-फिकेशन किया जा सके और उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। इनमें सब से पहले जरूरी है कि आप वोटर लिस्टों से उनके नाम हटायें। इनकी पहचान करें। फिर इनको आप एक विदेशी नागरिक के तौर पर, अनडिजायरेबल व्यक्ति के तौर पर इनकी घोषणा करें और दुनिया में जहां कहीं ये जाना चाहें वहां भेजने की व्यवस्था करें। दुनिया बहुत लबी है। अगर लिविंग स्पेस उन्हें चाहिए तो दुनिया में बहुत लिविंग स्पेस है और अब तो चन्द्रमा तक जाने की व्यवस्थायें हैं। जुपिटर अंतरिक्षयान के नजदीक तक जा रहे हैं। अमरीका से कहा जाए कि मदद की जाए और उन लोगों से कहा जाए कि इनको ले जाओ। इनको जीने के, रहने के लिए और स्थान की आवश्यकता है। हम भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन भारत में इनको मत बुलाइए। जो सामाजिक तनाव इस देश के अदर पैदा हुए हैं, जो क्राइम रेट्स बढ़े हैं और इसके साथ जो राजनैतिक परिवर्तन की जो आज सारी बात हो रही है और बृहत्तर बर्ग मानने की आज बात हो रही है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बार-बार पाकिस्तान के लोग बयान दे रहे हैं कि फलां-फलां हिस्सा अभी 1947 का अधूरा एजेंडा है। महोदया, मैं आपके माध्यम

से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी वही शरारत है, जिन्ना साहब पूरे आसाम को और पूरे बंगाल को पाकिस्तान में चाहते थे। यह आबादी का रूपांतर करके आबादी के अंदर एक विशेष प्रकार का मजहबी उन्माद पैदा करके और आसाम के बारे में और त्रिपुरा के बारे में मैं चेतावनी देना चाहता हूं। कि अगर आपने इस बिल को पास नहीं किया और अभी से कदम नहीं उठाए तो वह दिन दूर नहीं जबकि वहां के हालात काश्मीर घाटी के हालात से खराब होंगे। उत्तर-पूर्वांचल की सातों स्टेट्स के अंदर आज जो स्थिति है, मैं आप से कहूंगा कि आप वहां जाएं, उसका मुलाहजा फरमायें, उसे देखें और गौर से देखें कि क्या हो रहा है? अगर देश को अगर बचाना चाहते हैं तो इस विधेयक को पास करें।

महोदय, मैं शर्मा जी को फिर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण विधेयक द्वारा देश की बड़ी भारी ज्वलंत समस्या को सामने रखा है। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर घुसपैठ को रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जबकि देश में 1947 और उसके पहले के जैसे हालात, जिसमें कि मुस्लिम लीग जिस तरह की डिमांड किया करती थी, वह फिर पैदा हो जायेंगे। देश के सामने नये विभाजन का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से देश की रक्षा करने के लिए व देश की राजनीति और सेकुलर तानाबाना ठीक रखने के लिए इस बिल का पास करना बहुत जरूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): धन्यवाद जोगी जी। आपका भाषण बहुत संक्षेप में रहा।

श्री मोहम्मद सलीम—अनुपस्थित।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—अनुपस्थित।

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR (Assam): Madam Vice-Chairman, thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill.

While supporting the Bill, I would like to submit that when there is a lack of political will to implement the provisions of the various Acts and rules for the purpose of preventing the infiltration as well as the detection and deportation of foreign nationals, this Bill, if passed, would be only another addition to the plethora of Acts and rules already existing.

The Foreigners Act is adequate enough to deal with the problem, but unfortunately no attempt was made to bring the provisions of these Acts and rules into operation. On the other hand, the foreigners problem is being used for narrow political ends. Politicians are building up vote banks by encouraging infiltration, helping the foreign nationals in getting ration cards, getting them enrolled in voters list and actively helping them in encroaching upon Government lands, V.G.Rs, P.G.Rs., forest lands and lands in tribal belts and blocks.

When the situation became acute, the people of Assam started a mass movement under the leadership of the All-Assam Students' Union. This movement continued for six long years During this period these bows were called by all sorts of names. They were termed as parochial chauvanist, secessimists. Now after a lapse of ten years, we have come to realise that this is a real problem.

This mass movement led to the signing of the Assam Accord. This Accord made provisions for solving the foreigners problem. I would like to draw the attention of the House to some of the stipulations in the Accord While doing so. I would like to stress that this Accord has remained only on paper, without any endeavour on the part of the Government to fulfil the various provisions. This document was signed between the Government of Assam, the student leaders of Assam and the Central Government. In this Accord, it was stipulated like this:

"For purposes of detection and deletion of foreigners 1-1-1996 shall be the base date and year.

[Shri Tara Charan Majumdar]

All persons who came to Assam prior to 1.1.1966, including those amongst them whose names appeared in the electrol rols used in 1967 elections, shall be regularised.

Foreigners who came to Assam after 1-1-1966 (inclusive) and up to 24th March, 1971, shall be detected in accordance with the provisions of the Foreigners Act, 1946, and the Foreigners (Tribunals) Order, 1964.

Names of foreigners so detected will be deleted from the electoral rolls in force. Such persons shall be required to register themselves before the Registration Officers of the respective districts in accordance with the provisions of the Registration of Foreigners Act, 1939, and the Registration of Foreigners Rules, 1939."

"For this purpose, Government of India will undertake suitable strengthening of the governmental machinery". These things have never been done. Post 1-1-66 infiltrators were not detected. No register was drawn up. The Government cannot show that even a single name was registered with respect to persons who entered Assam after 1-1-1966. And, as to the stipulation that "the Government of India will undertake suitable strengthening of the governmental machinery", nothing was done. This agreement remains only on paper. No effect was given to the stipulations made herein.

Then, "On the expiry of a period of ten years following the date of detection, the names of all such persons which have been deleted from he electoral rolls shall be restored." Nothing was done. Again 'All persons who were expelled earlier, but have since re-entered illegally into Assam, shall be expelled." There is no record of the persons who have entered. So the question of expelling them does not arise. Further, "For-

ıo uo ɯɐssʎ oʇ ǝɯɐɔ oʍ sɹǝʌǝ

after March 25, 1971 shall continue to be detected, deleted and expelled in accordance with the law. Immediate and practical steps shall be taken to expel such foreigners." Nothing has been done. No foreigners have been expelled under this provision. On the other hand, the influx is increasing years after year.

It was stated by the Assam Chief Minister on the floor of the Assam Assembly that the number of foreign nationals at present is 30 lakhs. He made the statement on the floor of the House. The following day, under the leadership of one of the Congressmen, the Muslim Forum gave an open threat, "If you insist on making such statements, we will see that you are removed from your post within five minutes." Immediately thereafter, the Chief Minister altered his statement. He said, "I was misled by the intelligence report of the Government of India which stated that the number was that but, in fact, there is not a single foreigner in Assam." That was the statement he has been making since then.

Now, "The Government will give due consideration to certain difficulties expressed by the AASU/AAGSP regarding the implementation of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals Act, 1983.' Now, Madam, this IMDT Act is a great hindrance in the process of detcting and deporting foreigners. This Act provides that any citizen can file a complaint before a Tribunal, alleging that such and such a person is a foreigner. He has to file the complaint before a Tribunal, he has to collect all the evidence and he has to produce all the evidence! Is there any procedure like this in any other civilized democratic country? I don't think so.

SHRI VISHNU KANT SHASTRI: Not only that. He should be residing within three kilometres of the residence of the alleged foreigner.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: That is there; these provisions are known to you. My submission is, unless this Act is repealed, no amount of legislation or whatever it is will enable the Govt. drive out even a single foreigner from this land. If somebody can sneak into Assam, he cannot be reported under any circumstances. Somebody must come and produce evidence that a particular person is a foreigner and that evidence is available with him. Therefore, this Act was passed only to protect the foreigners.

Now, I don't know how the present Bill if passed into an Act, will be able to drive out the foreigners when this IMDT Act is in force. The first duty is to get this Act repealed. Unless you repeal this Act, you can do nothing for the persons who are in Assam. This is the position.

There are other stipulations also in the Assam Accord. Nothing has been achieved. No attempt has been made by the Government to implement the stipulations made in this Accord.

It has also been stipulated that specific complaints that may be made by the AASU and the AAGSP about irregular issuance of Indian Citizenship Certificates will be looked into. It has also been stipulated that the Government will arrange for the issue of citizenship certificates in future only by the authorities of the Central Government. I beg to draw the attention of the Members to the fact that in Assam even Ministers are issuing Citizenship Certificates. This is the position in spite of this stipulation.

It has also been stipulated that the international border shall be made secure against future infiltration by erection of physical barriers like walls, barbed wire fencing and other obstacles at appropriate places, that patrolling by security forces on land and riverine routes all along the international border shall be adequately intensified and that in order to further strengthen the security arrangements to prevent effectively future infiltration an adequate number of check-posts shall be set up. Nothing has been done. I assure the Members that nothing has been done. As a result, the infiltration is continuing unabated.

It has also been stipulated that besides the arrangements mentioned above and keeping in view security considerations, a road all along the international border shall be constructed so as to facilitate patrolling by security forces, that land between the border and the road would be kept free of human habitation, wherever possible, that riverine patrolling along the international border would be intensified and that all effective measures would be adopted to prevent infiltrators crossing or attempting to cross the international border. These stipulations have been made which remains on paper only Hon. Joshiji has stated that in Tripuar there is nothing called "border". It is open. Everybody can come and go.

It has also been stipulated that it will be ensured that relevant laws for prevention of encroachment on government lands and lands in tribal belts and blocks are strictly enforced and unauthorised encroachers evicted as laid down under such laws. Nothing has been done. I inform hon. Members that there has been increase in the forcible occupation of not only the government land, the VGRs and the PGRs but also especially the railway lands. The railway lands are full of infiltrators. Nothing has been done to evict them. All this happens because of political considerations. Everybody is interested in vote banks. They want votes. So, they don't want to disturb all these infiltrators.

It has also been stipulated that it will be ensured that the relevant law restricting acquisition of immovable property by foreigners in Assam is strictly enforced. Nothing has been

done. There is no law restricting foreigners from acquiring immovable property. In fact, our people are very poor. There has been transfers of lands. There is, what you call, "distress sale". You go to Assam. You will find that there is a lot of distress sale of lands and foreigners have taken over the lands. There is no law. In spite of the stipulation made in this Accord, nothing has been done.

Now, the position in Assam is that it is not a question of foreigners alone. The question is of losing the linguistic, cultural and social identity of the indigenous people of Assam and also of the entire North East. The apprehension is that the indigenous people will be swamped by outsiders, including foreigners. The example of Tripura is before us. Joshiji has referred to it. In Tripura the ratio of population was 30 per cent outsiders to 70 per cent indigenous people. Now the figure is quite opposite. The local population has been reduced to 30 per cent; and the foreigners population has increased to 70 per cent. So this apprehension is there in the minds of the people of the North-Eastern States and rightly so.

Recently in Arunachal Pradesh the students have started a movement. They said that the total population in Arunachal Pradesh is 8 lakhs, out of that 25 per cent are foreigners. There is also a students' movement in Meghalaya and Mizoram. If this problem is not properly tackled. then, you will find a bigger movement than the Assam movement. These people are under an apprehension that they will be swamped in the North-Eastern Region. Although that Region is very rich in natural resources, their economic condition is very bad. The trade, commerce and everything else are in the hands of the people from outside the region. These people do not show respect to the local language, culture and the way of life. In fact, the people of that region wonder whether the land mass to the East of Bengal is part and parcel of India or not. I want to ask whether the Government considers us to be part and parcel of India. I would like to know whether the Government is really concerned for the well-being of the people in this region and integrity of the country.

Now, I will just bring to the notice of the hon. Members, two of my personal experiences. In 1942, when there was the Second World War, every outsider of the region left the place and returned to their provinces. In 1962, when there was the Chinese aggression, Pandit Jawaharlal Nehru bade us good bye by saying, "My heart goes to the people of Assam". At that time all hte outsiders left the place as rats leave a burning ship. Nobody was to be found there. I would like to know whether the Government would really consider us to be part and parcel of this great land. I am not a supporter of secessionist movement. I am an old man of 75 years. Since 1938 I have seen the history I am a political sufferer. I had suffered imprisonment. Our people have faced all the sufferings. I would like to know whether the Government treats the landmass to the East of Bengal as part and parcel of this great country.

I want to mention in the House that our people are very suspicious of outsiders because they are not contributing anything towards the progress of this region. They are earning a lot of money by fair means or by dubious means. A visit to post offices will show that thousands of crores of rupees are sent to their native places. They do not allow us to develop. They do not invest any money or capital for the betterment of the people of that region. Thsi is the position.

I want to draw the attention of the House to this burning problem. Nobody is giving any importanc to it. All sorts of blame is being put on the people that they are secessionists and chauvinists. Now the country has realised it. Our Region is in much danger because the rest of the country does not suffer so much from the foreigners problem. There is no fear of losing the identity of the people in the rest of the country. But our fear is that we have already become a minority. We the Assamese have already become a minority. The immigrants who came from East Bengal have accepted the Assamese language as their mother tongue. About 50 lakhs of tea-garden labourers, who were indented into Assam, had accepted Assamese as their mother-tongue. These two sections have now helped us in maintaining our linguistic majority very slightly. These are the ground realities. I want Members to be serious. Be serious and try to think that this land mass to the east of West Bengal is part and parcel of the country and you should be prepared to take part in the sacrifice being made by our people.

With these words, I conclude. Thank you, Madam.

DR. B. B. DUTTA (Nominated): Madam, the issue which is now being discussed is a very sensitive one. In fact, whenever we start talking about infiltration, the whole atmosphere gets electrified and sometimes it becomes very difficult to have a dispassionate assesment of the situation. So, I would appeal to this House to kindly take whatever I am going to say not in a partisan spirit but in the light of the facts against the historical perspective.

The first point I would like to make is this. When the hon. Member, Shri Krishan Lal Sharmaji, moved this Bill, he made certain comments. For the sake of record, I would like to correct one misconception revealed by one comment he had made. If I remember correctly, the week before the last when he moved the Bill, he said that the whole problem arose because we accepted the two-nation theory and the partition of our country. Now, as far as we are concerned, I do not think that we accepted the two-nation theory. The partition was accepted because of expediency and not because the two-nation theory was accepted by the national leaders on the Indian side. The two-nation theory was forced by the Muslim League. But it was not accepted by us. There were certain coroliaries that followed from the two-nation theory. If we had accepted that the Hindus in India constituted one nation and the Muslims another and accordingly the country should be divided, well, in that case, we should have a Hindu Raj today, not a secular, democratic and socialist polity. That is what we are having today. Ours is a very vibrant democracy and is a functioning one. We are practising what we have been preaching. We cannot accept the view that we were subscribers to the two-nation theory.

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will you explain what is that 'expediency'?

DR. B. B. DUTTA: At that time, a civil war developed and lakhs of people were being massacred here and there. There were communal riots. And, an imperial power was presiding over there. We had to do something quickly. That is why it had to be accepted.

SHRI K. R. MALKANI (Delhi): It was after the Partition.

DR. B. B. DUTTA: But what happened before the Partition? It started from 1946 with the Direct Action in Calcutta. I do not like to go back to those details. But the facts remain as they do. These are matter of record.

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: The fact remains that the Partition was accepted.

DR. B.B. DUTTA: The Partition was accepted. What I am arguing is, the two-nation theory was not accepted by us.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please come back to your point.

DR. B.B. DUTTA: Madam, I am telling you, here is the misunderstanding. If you do not explain the perspective this infiltration problem will never be understood. It will always be misunderstood because the infiltration problem is being discussed from the angle of Assam, from the angle of Tripura and from the angle of certain tribal States. In this way, you cannot understand the problem of infiltration that has become a phenomenon in the Indian subcontinent today. It is not only confined to the eastern sector but it is also there in Rajasthan, in Western Uttar Pradesh, in Kasrmir and in Punjab. Therefore, the facts of history should be put in proper perspective and then we will understand what the problem is. What I am going to say is, let the perspective be made clear first. We are not subscriber to the two-nation theory. But the Muslim League was. What theory had been propunded by the Muslim League? Quarbani! When the questions were put to them, "What would happen to the millions of Muslims who would be living in an independent India?", they said: "They had to be given in Qurbani. We are giving them in Qurbani and they have to accept it for the sake of Islam." This was their theory. Their theory was very simple. But our theory is not like that. We have not given the minorities in Qurbani to Pakistan. We have not given the minorities in Qurbani in the Eastern Pakistan. This is not our theory. This is the first point. The second point is that those people who had made a conquest of Pakistan, those who are in power there, to them, the secular, democratic India remains a very big challenge and if you analyse the history of half a century, if you analyse the poltical events that took place in the other part of undivided India, then you will find that there was clamour for democracy but it was still being denied. Ultimately, we have come to a position that the fundamentalists, the fanatics, who made a conquest of Pakistan and who are still in power, they have taken the help of militants to remain in power. You will find that the real power in those areas is still in the hands of the military and the fundamentalists. It is they who have been dictating terms whether it is Bangladesh or Pakistan. Now, they will never be friendly to us. What conditions have been created by them? They have created an unbearable condition for the minorities who live there and that is the main thing which is not being discussed in India. If the minorities are not able to live peacefully in Bangladesh, then where will they go? May I remind that at the time of partition, the national leaders of India, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Govind Ballabh Pant, all of them had said and made a solemn promise that they were accepting the partition. But if the minorities, the non-Muslims, feel very insecure in other parts of the country, that is in Pakistan, then the doors of India would remain open. This was a solemn promise made by the national leaders. So, India is under a moral commitment that if these people find themselves in danger and their properties insecure in those areas and are not able to live there with dignity, then they have a right to cross over. We should not forget history. It is in this backgrond that you will find that over the decades, a continuous smigration of the minorities has taken place towards India because we have not been able to ensure enough protection for the minorities of Ban-

gladesh, the minorities of former East Pakistan because it is a foreign country. We were confused in our attitude and policies and still today we are in confusion. In fact, we should have devised our external policy in such a way that we are able to give some protection to the minorities and it is very much co-related to the protection, equal rights and dignity we want to give and we have been trying to give to the minorities here in India. It is in the interest of the minorities here that the minorities there should be protected. Now, these things are lost sight of. As a result, what had happened? After ten years of partition, we had about 22 per cent non-Muslim minorities in Bangladesh, that is the former East Pakistan. Now, what is the percentage? It is 10.5 per cent. Where have they gone? Why have they gone? They have come to India. Now I ask the second question: Can you throw them out? They have come over here decades back. They have settled. They have had their education there. They have made it their home. They have raised children. They have owned property. They have become voters. Suddenly, if you take a technical clue from the Constitution and say that they are covered by the definition 'foreign nationals', can you throw them out? It is going to be humanly impossible. In that case, you will herald a new revolution. There will be bloodshed. There will again be a civil war. That also you cannot do. Because of these realities when Bangladesh emerged following the revolution in 1971 in East Pakistan, at that time the Indira-Mujib Agreement stipulated: "Till this date, whoever have come into India are to be accepted as Indian citizens." There is no question of discrimination between the Hindus and Muslims. Whoever have come are to be accepted as Indian citizens. That is there. Now we should not question it, because it was agreed to. And not only that, the circumstances, the realities, the compelling realities are there. How can you throw them out, by agreeing to partition, whom you have kept on the other side—the people who fought, the people who died for the freedom of this country, the people who have sacrificed for the freedom of this country? We enjoy the fruits of freedom here and we say 'this is another country'! being. For example, take the situation in Bangladesh, West Bengal and Assamese areas. They are virtually one people. They are so close ethnically and linguistically. The same blood flows through their veins. They use the same language. The only difference is that the religion is different. There is no other difference. So, how can you do that?' I do not understand this thing.

Now, I come to the other side. See, these are all facts of history. I want to remind this because sometimes we confuse ourselves in giving our opinion. Now after this Agreement, the Indira-Mujib Agreement, when Bangladesh emerged, we had expected that Bangladesh fought for its independence against Pakistan, the issues were exploitation and religious fanaticism. That is why we helped Bangladeshis. They wanted to have democratic nation, they wanted to have a really free, secular and democratic nation and they did not have any commitment to religious fanaticism. That was the understanding, but now after Bangladesh has emerged, during the late seventies, during the eighties, a very disturbing trend has developed and that is that Bangladesh is being Islamised to a degree by the Islamic fundamentalists where the lives of the minorities have become much more insecure than they were during the East Pakistan days of united Pakistan. That is the situation that has now arisen. Now, the hon. Members respected Joshiji and others, have quoted from the General Secretary's report to the North-Eastern Congress Coordination Committee. I have authored this report myself. My

[Dr. B. B. Dutta]

colleagues have put their signatures. We have debated this report. I stand by each and every word of this report. The report should not be quoted out of context; that is what I would like to submit. In this report we have taken the issue as a national issue. It is not a question of the problem of Assam or Tripura or Bengal.

SHRI VISHNU KANT SHASTRI: Madam, he is raising a very important issue. The Minister is not listening to the views expressed by a Member of his own Party.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Minister Shastriji is saying that the Minister is not listening to the Member of his own Party. Will you please listen to him?

DR. B. B. DUTTA: Madam, we have not said in that report that so many infiltrators have come in West Bengal or in Assam or in Tripura because we do not have this figure. We do not have any such figure. So, it is wrong to say that in the tribal States of North-East or in Assam or in West Bengal, so many people have crossed the border. But we can understand that they have crossed the border in large number and come into India. We have written in our report that the Bangladeshi people who have come are not present only in the Eastern States but are also present in the other parts of the country. It is being admitted by the Bangladeshi intellectuals, the University teachers and others. They did not hide the fact. It is there. The question which I put is this: Can you solve this poblem of increasing migration or infiltration, in whatever term the Members from the other side may call it, without tracing the origin of the problem? If you go to the origin of the problem, if you go into the genesis of the problem, you can see that certain things are happening. I will give you one classic example. In 1965, when the India-Pakistan war broke out, the then President of Pakistan, General Ayub Khan, taking a cue from the Second World War when an ordinance was issued by the British Government, declared India as an enemy country and confiscated the properties of those people who had any of their family members residing in India. Now, there were quite a large number of families. There might be three brothers one came to Indian and had been living in India. Two brothers were working there and the properties were there. The share in the properties of the gentleman, who came to India, was declared as an enemy property and was confiscated and the Goverment of Pakistan took over that property. The Enemy Property Act, which was in operation since that time—it is a strange phenomenon that when Bangladesh emerged only the nomenclature of this Act was changed; but the substantive clauses of the Act remained and continue till today. Now they call it the Vested Property Act. This Vested Property Act, whose other name is the Enemy Property Act, was one of the major factors responsible for causing migration of a large number of minority people to India. My question is this: Why are you sleeping over it? Why should this Act be there? Nobody has ever raised these questions. What has the Indian High Commision in Dhaka been doing? Do they not know that the operation of this Act has been causing a lot of migration? I am not going into the details of this Act. I have got all the documents with me. If you require I will explain various aspects of this Act. I must inform the House that a retired Chief Justice and three other intellectuals, they are all Muslims—I don't have any hatred towards Muslims—I don't segregate Hindus and Muslims in that sense—came out and vociferously against this atrocious Act protested against the exploitative nature of this Act They said, "What is this? This is very unjust." Now, I am raising this

question: Why is the Government of India seeping over it? Wnat nas the External Affairs Ministry been doing? What is the Indian High Commission been doing in Dhaka? Let us have identity cards, let us invoke the deportation clauses and push them out. You push them out, they will come back. Where will they go? They have to live. They have to exist. They cannot sacrifice themselves at the altar of fighting between the fundamentalist groups. This is not being done. Nothing is being done. Now, the real battle is between the fundamentalists there and the fundamentalists here. For example, I will tell you what happened when the Babri Masjid affair arose. What was the response in Bangladesh? As a result of the demolition of that structure not less than 3,500 temples had been demolished and not less than 1,000 women had been raped in Bangladesh and people were coming in streams into India. This phenomenon has increased. Fundamentalism has increased further. Now, if you do something here, it will have a direct result there. Could you control those results? May I ask Hon. Member Joshiji who is a responsible Member of the House, "You did something here. But, could you prevent the results elsewhere? What could you do for the Hindus of Bangladesh?" You could not do anything. The fundamentalists in Bangladesh were very happy because fundamentalism in India is increasing. This inceases their strength. The secular democratic polity is a challenge to them because they had surrendered in favour of the progressive forces, those who want to live together as brothers for getting religious differences. But if the fundamentalist trend emerges in India, and even gets strengthened, the Islamic fundmentalists feel very happy. That is exactly what is happening now. Fundamentalism is on the increase in the sub-continent.

SHRI VISHNU KANT SHASTRI: I want to know one thing. What was the atmosphere there before the 5th December, till the 4th December?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आपका चांस जब आएगा तब बोलिएगा। उनको क्यों इन्टरेप्ट कर रहे हैं। जब आप एक घंटा बोले तब किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं?

SHRI B. B. DUTTA: Now, let us go to te origin. After Bangladesh has appeared in the political horizon as an independent country, the fundamentalists have estblished themselves and they are influencing the polity of that country. They are cultivating the anti-India politics and are trying to brainwash their people against India, though Bangladesh exists with Indian commodities from breakfast to lunch to dinner, from morning to night. But still the anti-India campaign is going on. All these things are happening. We are sitting idle. We are not doing anything. We have to do something in this regard. What can we do? We have to see that independent Bangladesh becomes equally prosperous. They have to be told that their standard of living can be raised, that that country can be industrialised. They should not be left at the mercy of so many other powers who are trying to dole out assistance of various kinds to dictate terms and use Bangaldesh as a bridgehead against India.

Now, what is the latest position? The ISI is operating there. It was not operating there earlier. Now, Pakistan has found Bangladesh to be an ideal canvas. The ISI is operating there. It is training the people there. It is training the people there. It has taken insurgent groups from India and is training them. They are trying to destabilise the entire North-East. They are trying to inject troubles into the North-East the way they hav been doing it in Kashmir. I agree that another Kashmir is in the offing. What are you doing?

[Dr. B. B. Dutta]

Should we allow a small country, a weak power, which is suffering from instability, which does not know what to do with itself, to do this? You talk to the Bangladesh leaders. I have talked to them for days together. They are in a dilemma. They do not know what to do. They are afraid of the fundamentalists. But they never speak it out. They are also afraid that if India lets them down, it will become difficult for them. The situation is like this. But in Delhi we hear statements like "Bangladesh is not a big power and we have no treats tour defence from that side, etc. But it is a terrible fact today. I must recall that during the Bangladesh war, our Prime Minister, the late Indira Gandhi told our Governor, Shri B. K. Nehru, "I know this county is going to be free. But I am telling you to day that this country is going to be a terrible headache for us. Here, so many forces will operate. I don't know what is going to happen." But I find now that there is not enough consciousness in Delhi, the centre of power, about the situation. Even the intelligence reports are ignored. Whatever reports come here there are not analysed properly (...*Time bell*...). It is a very serious situation of infiltration. It is a national problem. It is a micro problem. This problem has to be tackled by the Government of India, not by the Government of Assam, not by the Government of West Bengal, not by the States of the Eastern or the Western regions. This problem has to be fully analysed and understood. The problems are intensifying everyday. They have quoted from my report that even Muslims from Bangladesh are migrating. I have interviewed Muslims taking with me the correspondent of the Statesman. You go to Calcutta and travel from Calcutta towards the border, you will find that on both sides of the railway lines hundreds of thousands of Bangladeshis are living in Jhuggis. There are some Muslims, I believe, not many. I interviewed them. They are innocent people, very poor people. They did not have anything to live on. That is why they came here. They did not come to conquer India. If you cannot send the Hindus back to Bangladesh, how can you send the Muslims back, being a secular democratic country? How can you just single out Muslims and send them back? This is the question that has been raised. Let us be very free and frank while talking on such matters. We should not try to hide ourselves behind something. So, these are the problems that we have had. Now, that is why, I say, "Solve the problems of infiltration at the point of its origin." Where do the infiltrators come from? If the Bangladeshis are coming to India, then we should see that the causes for this are dealt with inside Bangladesh. This is not being done. So many tribal refugees have come from Bangladesh. What did you about those refugees? So many Chakmas are there. Recently, there was also the Supreme Court verdict on the Chakmas. I have got some papers. A lot of problems are there. I don't want to go into the details. But what I insist is that these matters should not be raised by students of this State or that State; I want our national leaders, all political parties, to put their heads together and see what the battle in the sub-continent about. The battle is between the fundamentalist forces operating from the Pakistani side and the secular democratic forces operating from the Indian side. Today, India, which stands out as the largest democracy in this vast South-Eastern region, is the number one target of those people who want theocracy to prevail in their countries. We are all against theocracy. We have become the target and that is the danger. Today, India's external policy should focus on how to save ourselves from theocratic onslaughts. These are being

aimed at from Pakistan and other neighbouring countries. They are pumping in money. They are pumping in arms and they are arming our own people inside our own territory. They are also arming people on the other side. These things are going on. Infiltration is very much there. Hindus are coming; Chistians are coming; tribals are coming and Muslims are also coming. All these people are crosing over to India. Muslims also come over here from Bangladesh for economic reasons. We cannot deny it. It will be very difficult to say what the exact number is. It is funy to say that so many lakhs and so many crores of people came. We know that it is a very large number; it is a substantial number and it can cause an upheaval in the structure of our society. It has created a lot of tension in Assam. It has created a lot of tension, now, in certain areas of West Bengal and it is going to create a lot of tension in the tribal areas of the Eastern region. So, it is we who are suffering. We are at the receiving end. What happens when something goes wrong in Burma? Muslims are sent back to Bangladesh. As a result, more Buddhists are being pushed into India. Some time back, a BBC correspondent coming from London told me, "This is what is happening. And your own country is sitting idle. What are you doing about it?" We don't talk about it because we say that this community will not like it and that community wil not like it. I think when we talk about the facts if we talk about what is happening in Bangladesh, even our Muslim brothers will agree that they are the facts. I happened to talk to some people belonging to Bangladesh when I met them in Calcutta. They didn't deny the fact. They say, "You have to do something." We have to sit together. This is a big problem. So, why should we insult the genius of the Muslim community by saying that if we talked about these things, then the Muslims would not vote for us? There is we speakout fact, then tion that if we speakout fact, then the Muslims will not vote for the Congress, the Muslims will not vote for the CPI(M), the Muslims will not vote for this or that party and so on. This is a wrong thing. This is an insult to the Muslim community. Whatever is happening in Bangladesh, it is the Muslim intellectuals who have written about it. Very recently, I must bring to your notice—I must pay a tribute for a book that was written by Ms. Taslima Nusreen titled 'Shame'. She has written some other books also. Whatever she has written in this book is based on the 100 per cent facts. I am telling you this because I was doing some work on the subject concerning migrants from Bangladesh. What a free and impartial account has been given in this book by this indomitable Lady writer of Bangaladesh. She is a Muslim Lady doctor aged only 31 or 32 years old. She is under death sentence from the Islamic fundamentalists. The fundamentalists have declared that she should be liquidated. So, you see, it is not a Hindu-Muslim question. It is the question of determined gangs of fundamentalists making an onslaught on the majority of people comprising. Hindu Muslims and everybody. That is why I say that the question of infiltration, the question of this kind of migration, is a very serious phenomenon obtaining in the Indian subcontinent after the partition. We should put them in proper perspective and take corrective measures. Let all the political parties combine together. Let all the leaders put their heads together and see how this situation can be remedied once for all.

Thank you.

श्री मोहम्मद सलीम : उपसभाध्यक्ष महोदया, जो बिल, जो विधेयक कृष्ण लाल शर्मा जी लाए हैं मैं उसे समझता हूं कि यह एक कम्प्लेक्स समस्या है, जटिल समस्या है और उसका हम जितना राजनीतिकरण कर रहे हैं उससे उस समस्या के हल के बजाए उसे और भी ज्यादा हम उलझा रहे हैं।

[श्री मोहम्मद सलीम]

[उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) पीठासीन हुए]

इस सदन में जब यह बात हो रही है–रास्ते में जो भाषण होता है वह अलहिदा बात है–सदन में भी उसे समझने के बजाए, कोई रास्ता निकालने के बजाए जो कि एक वास्तविक समस्या है आज हमारे देश के लिए कि विदेशी नागरिक घुसपैठ करते हैं, अनुप्रवेश करते हैं, मैं समझता हूं कि जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिएं लेकिन चिंतित होने के नाम पर हम रोटी सेंकने की कोशिश करते हैं हाथ को जलाकर। तो यह ठीक नहीं है। यह हाउस आफ एल्डर्स है। हमारे बुजुर्ग सदस्य इसे यहां लाए हैं। हमारे देश में हमने देखा है कि किस तरह से अनुप्रवेश का सवाल, फारेन नेशनल्स का सवाल आज चलाया गया है। पहले यह सवाल 70 के दशक में उठा था आसाम में, जो विदेशी घुसपैठ के नाम पर था। कुछ लोग ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं, हमारे कृष्ण लाल शर्मा जैसे समझदार लोग भी हैं जो उनकी जैसी समझ रखते हैं उन्होंने काफी उत्साह लिया, प्रोत्साहन भी लिया। लेकिन ऐसा भी लिखा हमारे अरुण शोरी जी ने, मैं नाम ले रहा हूं, मैं उन्हें बुद्धिजीवी मानता हूं। मैंने उनका एक लेख पढ़ा था। उस समय मैं कालेज का विद्यार्थी था। आसाम में जब विदेशियों को भगाओ के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ तो यहां लिखा गया कि आजादी के बाद यह पहला नौजवानों का सबसे सही और बेहतरीन आंदोलन देखने को मिल रहा है। उसका नतीजा उसके बाद में देखा गया कि किस तरह से कौन से रास्ते से या आसाम का रास्ता पकड़कर आज वह पूरे नार्थ ईस्ट में पहुंच गया। वह आंदोलन उसी से उठा होगा। इसी सवाल के साथ एक मुद्दा है, एक प्रश्न है। पूरे आसाम से शुरू हुआ विदेशियों के नाम पर और नौगांव में, नेल्ली में हम जानते हैं कि–किस तरह से मास ग्रेव में तब्दील हो गया जहां पर सैकड़ों आदमियों को बच्चों को कब्र में सुलाया गया। अब कब्र में सोने वाले विदेशी थे, परदेशी थे, असमिया थे, गैर असमिया थे, बंगला जुबान बोलने वाले थे, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ अपने बयान के शुरुआत में वार्निंग बेल की तरह यह कहना चाहता हूं कि यह कितना सेंसिटिव सवाल है, इसका अगर साम्प्रदायीकरण करेंगे, राजनीतिकरण करेंगे तो हमारी उलझन सुलझेगी नहीं। मैं मानता हूं कि अगर विदेश की ताकतें, चाहे उनके एजेंट्स, चाहे विदेशी नागरिक इस तरह से घुसपैठ करेंगे तो यह हमारे देश की हिफाजत के लिए, मजबूती के लिए परेशानी और भी बढ़ाते जायेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आये दिन हम ये बयान दें किसी के लिबास को देखकर, जुबान को देखकर, भाषा को देखकर। लोग इस बात को बाहर उछाल रहे हैं। अभी जरा कम हैं, सीमित हैं लेकिन पिछले 4–5 साल से खासकर आप देखेंगे कि जितनी भूख उतनी ही बात। कोई कहता है कि पांच लाख विदेशी, कोई कहता है 40 लाख, कोई कहता है एक करोड़, कोई कहता है दो करोड़ तो यह नीलामी है।

†[] Transliteration in Arabic Script.

کہ آزادی کے بعد یہ پہلا نوجوانوں کا سب سے صحیح اور بہترین آندولن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ اس کے بعد میں دیکھا گیا کہ کس طرح سے کون سے راستے سے یا آسام کا راستہ پکڑ کر آج وہ پورے نارتھ ایسٹ میں پہنچ گیا وہ آندولن اسی سے اٹھا ہوگا۔ اسی سوال کے ساتھ ایک مدعا ہے۔ ایک پرشن ہے۔ پورے آسام سے شروع ہوا ودیشیوں کے نام پر اور نو گاؤں میں۔ نیلی میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ماس گریو میں تبدیل ہو گیا۔ جہاں پر سینکڑوں آدمیوں۔ بچوں کو قبر میں سلایا گیا۔ اب قبر میں سونے والے ودیشی تھے۔ پردیسی تھے۔ آسامی تھے۔ غیر آسامی تھے بنگلہ زبان بولنے والے تھے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اپنے بیان کے شروعات میں وارننگ بیل کی طرح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا سینسیٹیو سوال ہے اس سوال کو اگر سامپردائی کرن کریں گے۔ راجنیتیکرن کریں گے تو ہماری الجھن سلجھے گی نہیں۔ میں مانتا ہوں اگر ودیش کی طاقتیں چاہے انکے آبجنٹس۔ چاہے ودیشی ناگرک اس طرح سے گھس پیٹھ کریں گے تو یہ ہمارے دیش کی حفاظت کے لیے مضبوطی کے لیے پریشانی اور بھی بڑھاتے جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئے دن ہم یہ بیان دیں کسی کے ہے۔ سدن میں بھی اسے سمجھنے کے بجائے کوئی راستہ نکالنے کے بجائے جو کہ ایک واستوک سمسیا ہے آج ہمارے دیش کے لیے کہ ودیشی ناگرک گھس پیٹھ کرتے ہیں۔ انو پرویش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بارے میں ہمیں چنتت ہونا چاہیے لیکن چنتت ہونے کے نام پر ہم روٹی سینکنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھ کو جلا کر تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہاؤس آف ایلڈرس ہے۔ ہمارے بزرگ سدسیہ اسے یہاں لائے ہیں۔ ہمارے دیش میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انو پرویش کا سوال۔ فارن نیشنلس کا سوال آج چلایا گیا ہے۔ پہلے یہ سوال ۷۰ کے دشک میں اٹھا تھا آسام میں۔ جو ودیشی گھس پیٹھ کے نام پر تھا۔ کچھ لوگ ایسے بدھی جیوی بھی ہیں۔ ہمارے کرشن لال شرما جیسے سمجھدار لوگ بھی ہیں جو ان کی جیسی سمجھ رکھتے ہیں انھوں نے کافی اتساہ لیا۔ پروتساہن بھی لیا۔ لیکن ایسا بھی لکھا ہمارے ارون شوری جی نے۔ میں نام لے رہا ہوں۔ میں انھیں بدھی جیوی مانتا ہوں میں نے ان کا ایک لیکھ پڑھا تھا۔ اس وقت میں کالج کا ودیارتھی۔ آسام میں جب ودیشیوں کے بھگاؤ کے نام پر آندولن شروع ہوا تھا تو یہاں لکھا گیا

श्री मोहम्मद सलीम : मुरली मनोहर जोशी जी ने भी अभी कहा था। लेकिन उनकी प्रेस कान्फ्रेंस जब हुई थी, दो साल पहले तो उस प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने दो करोड़ कहा था। मैंने इसलिए नीलामी कहा कि वे विभिन्न संस्थायें हैं, नेता है, व्यक्ति है, बुद्धिजीवी हैं और वे सब इस तरह से आंकड़ों के बारे में बड़ा बाजार में जैसे नीलामी होती है उस तरह से नीलामी के बाजार में उतरे हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : मुरली मनोहर जोशी जी ने भी अभी कहा था। लेकिन उनकी प्रेस कान्फ्रेंस जब हुई थी, दो साल पहले तो उस प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने दो करोड़ कहा था। मैंने इसलिए नीलामी कहा कि वे विभिन्न संस्थायें हैं, नेता है, व्यक्ति है, बुद्धिजीवी हैं और वे सब इस तरह से आंकड़ों के बारे में बड़ा बाजार में जैसे नीलामी होती है उस तरह से नीलामी के बाजार में उतरे हैं।

और हम समझते है यहां पर अनुप्रवेश या विदेशी घुसपैठ का मामला नहीं, वह नीलाम के बाजार में नीलामी की जा रही है कि हम किस तरह से सत्ता के इर्द-गिर्द आ जायें उसके लिए हम जैसे कभी मंदिर के सवाल को, कभी मस्जिद के सवाल को, कभी किसी सवाल को ले करके जिस तरह से उभारते हैं, उछालते हैं, उसी तरह से अनुप्रवेश के मामले को, घुसपैठ को और विदेशी नागरिक के बारे में इसको उठाया गया। महोदय, आपको यह मालूम है अगर दक्षिण में इस तरह से पश्चिम से पूर्व तक समुद्र है तो फिर पश्चिम से पूर्व तक पूरे उत्तर के हिस्से में हमारा विदेश का जो दूसरे मुल्क हैं चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह अफगानिस्तान हो, चाहे चाईना हो, चाहे वह बर्मा हो, चाहे बंगलादेश हो, बंगलादेश के लिए सवाल यह है कि उसके इर्द-गिर्द में हमारा हिन्दुस्तान है। सिर्फ हमारा जो प्रांत पश्चिमी बंगाल है उसका ही बार्डर 2145 किलीमीटर लंबा है और जो घुसपैठ का मामला है, जैसा मैंने कहा कि यह वास्तव में एक समस्या है, यह कोई राजनीति करने का साधन नहीं है। इसको अगर हम सुलझाना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा होशियारी से भी काम लेना चाहिए और वह होशियारी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि खास कर जो गलत प्रचार है उससे पहले डरना चाहिए। मैंने नीलामी के बारे में इसलिए

लिबास को देखकर, जबान को देखकर, भाषा को देखकर लोग इस बात को बाहर उछाल रहे हैं, भी ज़रा कम है सेमत है, लेकिन पिछले ४-५ साल से खास कर आप देखेंगे कि कितनी भीड़ इतनी ही बात। कोई कहता है कि ५ लाख बंगलादेशी कोई कहता है ४० लाख कोई कहता है एक करोड़ कोई कहता है दो करोड़ तो यह नीलामी है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्त : (मध्य प्रदेश) : आप कितना कहते हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : सुनिए। अभी तो मैंने शुरू ही किया है। मैंने अब तक आपकी ही बात की है और आप अपनी बात में इतना गुस्सा करेंगे तो मेरी बात में क्या करेंगे आप।

श्री नारायण प्रसाद गुप्त : आप अपना भी बता दीजिए मेहरबानी करके।

श्री मोहम्मद सलीम : मुरली मनोहर जोशी जी ने भी अभी कहा था। लेकिन उनकी प्रेस कान्फ्रेंस जब हुई थी, दो साल पहले तो उस प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने दो करोड़ कहा था। मैंने इसलिए नीलामी कहा कि वे विभिन्न संस्थायें हैं, नेता है, व्यक्ति है, बुद्धिजीवी हैं और वे सब इस तरह से आंकड़ों के बारे में बड़ा बाजार में जैसे नीलामी होती है उस तरह से नीलामी के बाजार में उतरे हैं।

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

कहा जो चीज हाथ से टटोल कर देख ली जा सकती है जो लोग उसके बारे में भी गलत प्रचार करते हैं, जैसे कि काश्मीर के मंदिर और मस्जिद तोड़ने के बारे में है। आप जानते हैं जो जाकर गिनकर आपको बताया जा सकता है कि एक, दो, तीन, चार, पांच या दस इतने मस्जिद टूटे हैं, उस बारे में जो लोग पूना में एक कहते हैं, बालक्रा में दो कहते हैं और दिल्ली में आकर कुछ और कहते हैं, चुनाव के मौके पर और कुछ कहते हैं वह बंगलादेशी घुसपैठ के बारे में या फारेन नेशनल्ज के बारे में चार लाख से दो करोड़ तक का आंकड़ा भी पेश करते रहेंगे, बाजार में बेचते रहेंगे। इसमें हमारा कोई संदेह नहीं है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : कृपया आप अपना मत तो बताइए कि वहां कितने हैं? आप इतना तो बताइए कि आप कितना बताते हैं।

श्री मोहम्मद अलीम : आप धैर्य से सुनिए। जरा धैर्य रखिए। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। शास्त्री जी को मालूम है कि हम लोग नीलामी के बाजार से दूर रहते हैं।... **(व्यवधान)** तो मैं यह कह रहा था... **(व्यवधान)** महोदय, मैं जरा आपकी सुरक्षा चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : आप पूर्ण सुरक्षित हैं।

श्री मोहम्मद अलीम : महोदय... (व्यवधान) यह बात सुनने के लिए तीन बार नीलामी कहा कि आज उनकी दिक्कत यह है कि सौदा नहीं है जिसे वह नीलाम करेंगे। उनको नए सौदे की तलाश है और खास कर पश्चिमी बंगाल, जहां से मैं आता हूं, वह बंगाल जहां विद्यासागर, राम मोहन, रवीन्द्र नाथ, काजी नजरुल इस्लाम ये बताकर गए हैं, विवेकानन्द, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कि मंदिर के नाम पर बाजार में नीलाम करने से नीलामी नहीं चलेगा और इसलिए बंगाल में आपको खासकर तब मुरली मनोहर जोशी जी बोल रहे थे, जब कृष्ण लाल शर्मा जी बोल रहे थे पूरे देश के घुसपैठियों के बारे में, फारेन नेशनल्ज के बारे में आप बात करते-करते लेकिन आप जो पिन प्वाइंट करते हैं वह बंगाल के बारे में कहते हैं, इसलिए कि वहां अगर नीलामी के बाजार में आप उतरेंगे तो वहां मंदिर और जाति-पाति के बारे में आपकी नीलामी नहीं बिकेगी। इसलिए नए सौदे की तलाश है और उस सौदे के लिए आपके लिए सब से अच्छा रेडीमड मैटीरियल अनुप्रवेश और फारेन नेशनल्ज का मिला है... **(व्यवधान)** वह शास्त्री जी आप बंगाल से आए हैं। आप खुद जानते हैं आप वहां सत्य बेचते हैं या और कुछ बेचते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि यह राजनीतिक सौदेबाजी का सवाल नहीं है और न यह सिर्फ बंगाल का मामला है और बंगलादेश का मामला है, न साउथ एशिया का मामला है, पूरे विश्व में आप अगर मानव इतिहास देखेंगे तो विश्व के एक प्रांत से दूसरे प्रांत लोग पहुंचे हैं। माइग्रेशन हुआ है। जैविक कारण से, मानविक कारण से, आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, राजनीतिक कारण से और आप यह थ्यौरी देना चाह रहे हैं कि यह धार्मिक कारण से हो रहा है। जब यूरोप से लोग जाकर अमरीका में बसे, कनाडा में बसे, न्यूजीलैंड में बसे, आस्ट्रेलिया में बसे, हमारे हिन्दुस्तान से लोग गए, एशिया से गए, अफ्रीका में बसे, कनाडा में बसे, आस्ट्रेलिया में बसे, आपकी अगर थ्यौरी हम मान लेंगे तो उसे आप बंगलादेशी कहेंगे। उसे आप संख्या जो है, आबादी जो है, उसकी संख्या को परिवर्तन करके वहां कुछ घुसपैठी करके अंदर से मुतखिल करने के लिए कोशिश किया गया। यह एक इंटरनेशनल फिनामिनन है जिसमें हमेशा ऐसा होता है कि अच्छी आर्थिक अवस्था से लोग बिगड़ी हुई आर्थिक अवस्था से मायग्रेट करते हैं जैसेकि इंसानी सभ्यता से पहले जानवरों ने ऐसा किया कि एक जंगल में जब खुराक की कमी हुई, जब उनको रहने की दिक्कत हुई, जैसेकि आग लग गई, तो वे हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ गए और माफ कीजिए उस समय उनका कोई धर्म नहीं था। वह किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं जाते थे। अगर उनका धर्म था, तो वह जैविक धर्म था कि खराक की तलाश में, खाने की तलाश में उन्हें जाना पड़ता था इसी तरह सभ्यता एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती गई, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि बीसवीं

श्री मोहम्मद अलीम

सदी के आखिर में साइंस, टैक्नालोजी और इनफार्मेशन का इतना एक्सपोजर होने के बाद भी हम जैविक, धर्म और पुरानी सभ्यता के इतिहास को नहीं पढ़ते बल्कि हम उसे गलत कहकर, भावना के आधार पर गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं। लोगों की भावनाओं को छूना चाहते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मझे इसी से आपत्ति है। आप वास्तविकता की बात कीजिए। लेकिन जो घसपैठ हो रही है, हम उसका विरोध करते हैं और इस सदन में कोई ऐसा नहीं है जोकि यह कहेगा कि हिन्दुस्तान में गैर-हिंदुस्तानी की आबादी बढ़ जाए और वह घसपैठ करें। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी इस बीसवीं सदी के आखिर में कुछ इंटरनेशनल लाज हैं– पासपोर्ट है, वीसा है। उस सब को इंकार कर के लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर बठ जायेंगे तो वह कोई सभ्यता का पुराना इतिहास तो नहीं है। अभी हम बीसवीं सदी में रहते हैं जिसमें कि कुछ इंटरनेशनल लाज हैं और उनके आधार पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज भी हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं या कनाडा में जाते हैं तो बहुत से प्रबंध हैं, बहुत सी पाबंदी है और उसके तहत वह एक जगह से दूसरी जगह मायग्रेट करते हैं। वहां पर जाकर कार्ड-होल्डर बनते हैं और पासपोर्ट लेते हैं, वीसा लेते हैं।

महोदय, मैंने अभी पश्चिमी क्षेत्र का बाडर का दौरा पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से किया, तो वहां ऐसा टरेन है कि चाहे जैसलमेर का रेत हो, डेजर्ट हो। वह हमारी बार्डर के उस पार मैप में देखने को मिला। वहां स्थिति ऐसी है और आबादी के हिसाब से इतने कम लोग रहते हैं, लेकिन जहां आबादी है वहां कुछ-न-कुछ टाउंस है, शहर भी हैं। पंजाब में कांटेदार तार लगाकर पाबदी लगाने की कोशिश की गयी है। फिर जम्मू-कमीर में में यह सवाल आता है कि घुसपैठ हो रही है। औजार लेकर, ट्रेनिंग लेकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां आबादी है, गांव है और एक जैसे लोग एक जगह पर बसते हैं, वहां साइंस ने भी कोई ऐसी चीज ईजाद नहीं की है कि धर्म के नाम पर आप एक-दूसरे में फर्क चेहरा देखकर कर सकें। तो आप पूरा नार्थ-ईस्ट ले लें, आसाम में, त्रिपुरा में, ईस्ट बंगाल या वेस्ट बगाल ले लें तो वहां जो लोग बसते हैं वह सदियों से एक जैसे बसे हुए हैं, उन्हें वही राजनीतिक कारण या सांप्रदायिक कारण से जो लोग इस सभ्यता के शुरूआत से एक साथ रहते थे और जिनका कि इतिहास एक है, समाज एक है, लिवास एक है, खुराक है, चेहरा एक है, उनमें हम राजनीति और कम्युनिलिज्म को मिलाकर देश बांट देते हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। उसके बाद मैप है। आप सब कुछ एक साथ रहने के बावजूद भी अलहदा देश के नागरिक हैं, लेकिन जो मैप है वह तो दिल्ली या कलकत्ता में है। जो गांव की आबादी है जैसेकि ईस्टन बार्डर में आप जाएगे, नाथ-ईस्ट के बार्डर में जाएगे तो पता नहीं चलेगा कि कौनसा हिन्दुस्तान है और कौनसा पाकिस्तान है। वहां उस तरह से फक नहीं किया जा सकता। उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां जो बाडर का माइल पोस्ट है, अगर वह नहीं रहेगा या जैसे उनकी तरफ से बी. डी. आर. पोस्ट है बांग्लादेश और हिंदुस्तान का, तो पहले जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान है। उस तरह से वहां फक नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मैंने त्रिपुरा में देखा है, आसाम में देखा है और बगाल में देखा है। वहां बी. एस. एफ. है, लेकिन वहां ऐसे लोग भी दिखायी देते हैं कि सुबह इधर से उधर गए, सारा दिन काम किया और लौटकर फिर चले गए। वहां उनके लिए कोई पासपोट या वीसा नहीं है। फिर भी यहां के लोग वहां जाते हैं, सामान खरीदते हैं और यहां चले आते हैं। यह दिक्कत है और उसके लिए रिस्ट्रक्शन करना जरूरी है। हमने जब देश बांट दिया है और वह अलहदा देश है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक पोलिटिकल बिल की जरूरत होती है और उसकी फिजिबिल्टी की जरूरत है कि कैसे उसे इम्पोज कर पाएगे। हम यहां केवल एक बिल पास करके या विधेयक पास करके उसकी नहीं कर सकते। हम उसे राजनेतिक वातावरण से मोड़कर उसका सांप्रदायीकरण करके दिक्कतें ही खड़ी कर सकते हैं, उसका कोई हल नहीं कर सकते।

چاہتا ہوں کہ خاص کر جو غلط پرچار ہے اس سے پہلے ڈرنا چاہیے۔ میں نے نیلامی کے بارے میں اس لیے کہا کہ جو چیز ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھی جا سکتی ہے جو لوگ اس کے بارے میں بھی غلط پرچار کرتے ہیں جیسے کہ کشمیر کے مندر اور مسجد توڑنے کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں جو جا کر گن کر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ ایک دو تین چار پانچ یا دس اتنے مسجد ٹوٹے ہیں اس بارے میں جو لوگ پونہ میں ایک کہتے ہیں۔ کلکتہ میں دو کہتے ہیں اور دلّی میں اگر کچھ اور کہتے ہیں۔ چناؤ کے موقع پر اور کچھ کہتے ہیں وہ بنگلہ دیشی گھس پیٹھ کے بارے میں یا فارن نیشنلس کے بارے میں چار لاکھ سے دو کروڑ تک کا آنکڑا بھی پیش کرتے رہیں گے۔ بازار میں بیچتے رہیں گے۔ اس میں ہمارا کوئی سند نہیں ہے۔

شری نارائن پرساد گپتا: کر پیا آپ اپنا مت تو بتایئے کہ وہاں کتنے ہیں۔ آپ اتنا تو بتایئے کہ آپ کتنا بتاتے ہیں۔

شری محمد سلیم: آپ "دھیریے" سے سنیے۔ ذرا "دھیرئے" رکھیے۔ آپ تھوڑا سا دھیریے رکھیے۔ شاستری جی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ نیلامی کے بازار سے دور رہتے ہیں۔ "مداخلت"۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا... "مداخلت"... مہودے۔ میں ذرا آپ کی سرکشا چاہوں گا۔

شری محمد سلیم "جاری": اور ہم سمجھتے ہیں یہاں پر انوپرویش یا ودیشی گھس پیٹھ کا معاملہ نہیں۔ وہ نیلام کے بازار میں نیلامی کی چار ہی ہے کہ ہم کس طرح سے سستہ کے ارد گرد جائیں اس کے لیے ہم جیسے کبھی مندر کے سوال کو کبھی مسجد کے سوال کو۔ کبھی کسی سوال کو لے کر جس طرح سے ابھارتے ہیں۔ اچھالتے ہیں اسی طرح سے انوپرویش کے معاملہ کو گھس پیٹھ کو اور ودیشی ناگرک کے بارے میں اس کو اچھالا گیا۔ مہودے آپ کو یہ معلوم ہے اور دکشن میں اس طرح سے پشچم سے پورب تک سمندر ہے تو پھر پشچم سے پورب تک اتر کے حصے میں ہمارا ودیش کا جو دوسرے ملک ہیں چاہے وہ پاکستان ہو۔ چاہے وہ افغانستان ہو۔ چاہے چائنا ہو۔ چاہے برما ہو۔ چاہے بنگلہ دیش ہو۔ بنگلہ دیش کے لیے سوال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد میں ہمارا ہندوستان ہے۔ صرف ہمارا جو پرانت پشچمی بنگال ہے اس کا ہی بارڈر ۲۱۴۵ کلومیٹر لمبا ہے۔ اور جو گھس پیٹھ کا معاملہ ہے جیسا میں نے کہا کہ یہ واستو میں ایک سمسیہ ہے۔ یہ کوئی راج نیتی کرنے کا سادھن نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم سلجھانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا ہوشیاری سے بھی کام لینا چاہیے اور وہ ہوشیاری کے بارے میں یہ کہنا

وہ شاستری جی آپ بنگال سے آئے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں آپ وہاں ستیہ بیچتے ہیں یا اور کچھ بیچتے ہیں۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ راج نیتی سودے بازی کا سوال نہیں ہے۔ نہ یہ صرف بنگال کا معاملہ ہے اور نہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہے۔ نہ ساؤتھ ایشیا کا معاملہ ہے۔ پورے وشو میں آپ اگر مانو اتیہاس دیکھیں گے تو وشو کے ایک پرانت سے دوسرے پرانت لوگ پہنچتے ہیں۔ مائیگریشن ہوا ہے۔ جیسوک کارن سے۔ مانویک کارن سے۔ آرتھیک کارن سے۔ سماجیک کارن سے۔ راجنیتک کارن سے اور آپ یہ تھیوری دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ دھارمیک کارن سے ہو رہا ہے۔ جب یورپ سے لوگ جا کر امریکہ میں بسے۔ کناڈا میں بسے۔ نیوزی لینڈ میں بسے۔ آسٹریلیا میں بسے۔ ہمارے ہندوستان سے گئے۔ ایشیا سے گئے۔ افریقہ میں بسے۔ کناڈا میں بسے۔ آسٹریلیا میں بسے۔ آپ کی اگر تھیوری ہم مان لیں گے تو اسے آپ بنگلہ دیشی کہیں گے۔ اسے آپ سنکھیا جو ہے آبادی جو ہے اس کی سنکھیا کو پریورتن کر کے وہاں کچھ گھس بیٹھی کر کے اندر سے منتقلی کرنے کے لیے کوشش کیا گیا۔ یہ ایک انٹرنیشنل فینامینن ہے جس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی آرتھیک اوستھا سے لوگ بگڑی ہوئی

اپ سبھاادھیکش "شری ستیش اگروال": آپ بولن سرکشت ہیں۔

شری محمد سلیم: مہودے ... "مداخلت"۔۔ یہ بات سننے کے لیے تین بار نیلامی کہا کہ آج ان کی دقت یہ ہے کہ سودا نہیں ہے جسے وہ نیلام کریں گے ان کو نئے سودے کی تلاش ہے اور خاص کر پشچمی بنگال جہاں سے میں آتا ہوں۔ وہ بنگال وہاں ودیاساگر۔ رام موہن روبیندر ناتھ۔ قاضی نظرالاسلام یہ بتا کر گئے ہیں۔ وویک آنند۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کہ مندر کے نام پر بازار میں نیلام کرنے سے نیلامی نہیں چلے گا اور اس لیے بنگال میں آپ کو خاص کر تب موریلی منوہر جوشی جی بول رہے تھے۔ جب کرشن لعل شرماجی بول رہے تھے پورے دیش کے گھسپیٹھیوں کے بارے میں۔ فارن نیشنلز کے بارے میں آپ بات کرتے کرتے۔ لیکن آپ جو پوائنٹ کرتے ہیں وہ بنگال کے بارے میں کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں اگر نیلامی کے بازار میں آپ اتریں گے تو وہاں مندر اور جات پات کے بارے میں آپ کی نیلامی نہیں بکے گی۔ اس لیے نئے سودے کی تلاش ہے اور اس سودے کے لیے۔ آپ کے لیے سب سے اچھا ریڈی میڈ میٹریل الوپردیش اور فارن نیشنلز کا ملا ہے۔۔ "مداخلت"۔۔

ہماری اس بیسویں صدی کے آخر میں کچھ انٹرنیشنل لاز ہیں: پاسپورٹ ہیں۔ ویزا ہیں۔ اس سب کو انکار کر کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آکر بیٹھ جائیں گے تو وہ کوئی سبھیتا کا پرانا اتہاس تو نہیں ہے۔ ابھی ہم بیسویں صدی میں رہتے ہیں جس میں کہ کچھ انٹرنیشنل لاز ہیں اور ان کے آدھار پر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے لوگ امریکہ جاتے ہیں۔ میڈیسٹ جاتے ہیں یا کناڈا میں جاتے ہیں تو بہت سے پر بندھ ہیں۔ بہت کی پابندی ہے اور اس کے تحت وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر جا کر کارڈ ہولڈر بنتے ہیں اور پاسپورٹ لیتے ہیں۔ ویزا لیتے ہیں۔

مہودے۔ میں نے ابھی پچھلی اکشیتر کا بارڈر کا دورہ پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے کیا تو وہاں ایسا ٹرین ہے کہ چاہے جیسلمیر کا ریت ہو۔ ڈیزرٹ ہو۔ وہ ہماری بارڈر کے اس پار ریپ میں دیکھنے کو ملا۔ وہاں استھتی ایسی ہے اور آبادی کے حساب سے اتنے کم لوگ رہتے ہیں، لیکن جہاں آبادی ہے وہاں کچھ نہ کچھ ٹاؤنس ہیں۔ شہر بھی ہیں۔ پنجاب میں کانٹے دار تار لگا کر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر جموں کشمیر میں یہ سوال آتا ہے کہ گھس بیٹھ ہو رہی ہے۔ اندازے کر۔ ٹریننگ لے کر گھس بیٹھ آرتھیک اوستھا سے مائیگریٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ انسانی سبھیتا سے پہلے جانوروں نے ایسا کیا۔ کہ ایک جنگل میں جب خوراک کی کمی ہوئی جب ان کو رہنے کی دقت ہوئی۔ جیسے کہ آگ لگ گئی تو وہ ہمیشہ ایک طرف سے دوسری طرف گئے۔ اور معاف کیجیے اس سمے ان کا کوئی دھرم نہیں تھا۔ وہ کسی دھارمک درشٹی کون سے نہیں جاتے تھے۔ اگر ان کا دھرم تھا تو "جیسک" دھرم تھا۔ کہ خوراک کی تلاش میں کھانے کی تلاش میں انھیں جانا پڑتا تھا۔ اسی طرح سبھیتا ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑھتی چلی گئی۔ لیکن آپ سمجھا دھیکش مہودے۔ افسوس کی بات ہے کہ بیسویں صدی کے آخر میں سائنس ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کا اتنا ایکسپوژر ہونے کے بعد بھی ہم "جیسوک" دھرم اور پرانی سبھیتا کے اتہاس کو نہیں پڑھتے بلکہ ہم اسے غلط کہہ کر بھاؤنا کے آدھار پر غلط طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی بھاؤناؤں کو چھونا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھا دھیکش مہودے کیجیے اسی سے آپتی ہے۔ آپ واستویکتا کی بات کیجیے۔ لیکن جو گھس بیٹھ ہو رہی ہے ہم اس کا ورودھ کرتے ہیں۔ اور اس سدن میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ یہ کہے گا کہ ہندوستان میں غیر ہندوستانی کی آبادی بڑھ جائے اور وہ گھس بیٹھ کرے۔ آپ سمجھا دھیکش مہودے

جو بارڈر کا فائنل پوسٹ ہے اگر وہ نہیں ہے گا یا جیسے ان کی طرف سے بی۔ ڈی۔ آر پوسٹ ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کا۔ تو پہلے جیسا ہندوستان پاکستان ہے۔ اس طرح سے وہاں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے میں نے تریپورہ میں دیکھا ہے۔ آسام میں دیکھا ہے اور بنگال میں بھی دیکھا ہے۔ وہاں بی۔ ایس۔ ایف ہے۔ لیکن وہاں ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں کہ صبح ادھر سے ادھر گئے۔ سارا دن کام کیا اور لوٹ کر پھر چلے گئے۔ وہاں انکے لیے کوئی پاسپورٹ یا ویزا نہیں ہے۔ پھر بھی یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ سامان خریدتے ہیں اور یہاں چلے آتے ہیں۔ یہ دقت ہے اور اس کے لیے ریسٹرکشن کرنا ضروری ہے۔ ہم نے جب دیش بانٹ دیا ہے اور وہ علیحدہ دیش ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے لوک پالیٹیکل بل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی فزیبلٹی کی ضرورت ہے۔ کہ کیسے اسے امپوز کر پائیں گے۔ ہم یہاں کیوں یہاں ایک بل پاس کر کے یا دو چیک پاس کر کے اس کو نہیں کر سکتے۔ ہم اسے راج نیتک واتاورن سے موڑ کر سامپردائن کرن کر کے دقتیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی حل نہیں کر سکتے۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARAL): Would you like to conclude or continue in the next session?

کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاں آبادی ہے گاؤں ہے اور ایک جیسے لوگ ایک جگہ بستے ہیں وہاں سائنس نے بھی کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی ہے کہ دھرم کے نام پر آپ ایک دوسرے میں فرق چہرہ دیکھ کر کر سکیں۔ تو آپ پورا ناروتھ ایسٹ لے لیں۔ آسام میں تریپورہ ہیں۔ ایسٹ بنگال یا ویسٹ بنگال لے لیں تو وہاں جو لوگ بستے ہیں وہ صدیوں سے ایک جیسے بسے ہوئے ہیں انھیں وہی راجنیتک کارن یا سامپردائیک کارن سے جو لوگ اس سمسیا کی شروعات سے ایک ساتھ رہتے تھے اور جن کا کہ اتہاس ایک ہے۔ سماج ایک ہے۔ لباس ایک ہے۔ خوراک ایک ہے۔ چہرہ ایک ہے ان میں ہم راج نیتی اور کمیونلزم کو ملا کر دیس بانٹ دیتے ہیں میں اتہاس میں نہیں جانا چاہتا۔ اسکے بعد میپ ہے۔ آپ سب کچھ ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی علیحدہ دیس کے ناگریک ہیں لیکن جو میپ ہے وہ تو دلی یا کلکتہ میں ہے۔ جو گاؤں کی آبادی ہے جیسے کہ ایسٹرن بارڈر میں آپ جائیں گے۔ ناروتھ ایسٹ کے بارڈر میں آپ جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ہندوستان ہے۔ اور کون سا پاکستان ہے۔ وہاں اس طرح سے فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اب سجاد ریکشن ہونے وہاں

SHRI MD. SALIM: How can I conclude?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL). You can conclude. Or, will you continue in the next session?

SHRI MD. SALIM: It is a Bill; no problem. I will continue in the next session.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Okay, so the discussion on this Bill will continue. Now we have got Special Mentions and the Copywright (Amendment) Bill.
(*Interruptions*)...

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे जाना है हवाई जहाज से, इसलिए मुझे पहले बोलने का मौका दिया जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं भी यही कोशिश कर रहा हू कि हवाई जहाज की गति से सारा काम निपटा दें । बैठिए, आप । एक सेकेण्ड, प्लीज । यह कापी राइट (अमेंडमेंट) बिल..... (**व्यवधान**).....

SHRI J. S. RAJU: Only three speakers are left, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Just a minute. We have got three more items to be disposed of. One is the debate on the Ministry of Health and Family Welfare. No. 2 is Special Mentions. No. 3 is the Copyright (Amendment) Bill. I will take the consensus of the House. So far as the Copyright (Amendment) Bill concerned, Kumari Selja has been waiting for long. I have sympathy for her because she is the youngest in the whole team. Moreover, my daugter-in-law's name also is Selja. So I have got some sympathy for her. Therefore, if the House agrees, we can dispose of this Bill first.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्री सुरेश पचौरी : सर, विदआउट डिसक्शन कानून पास होगा, अगर इतनी सिम्पैथी है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : नहीं, नहीं । अकेले आपकी राय से पचौरी साहब कुछ नहीं होगा । अगर आप सहयोग देंगे तो फिर स्पेशल मेंशन में आपको अच्छा समय मिल जाएगा ।

I will be very liberal, you rest assured. And we have to hear the Health Minister on a very vital subject, on which Mrs. Jayanthi Natarajan was speaking so vigorously. Other Members also would like to speak on that. So, we will be having a free time then.
...(*Interruptions*)...

श्री सुरेश पचौरी : सर, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि कापी राइट बिल पहले पास करना है तो विदआउट डिसक्शन उसको पास कर लें । स्पेशल मेंशन से ज्यादातर मैम्बर का संबंध है उनको भी जाना है, इसलिए बिल के बाद स्पेशल मेंशन टेकअप कर लीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : मतलब बिल के बाद इसको लें और हैल्थ मिनिस्टरी का बाद में लें । ठीक है ?

श्री सुरेश पचौरी : जी हां ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : तो सदन सहमत है ?

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सुरेश पचौरी जी ने जो सुझाव दिया है, मैं इसका समर्थन करती हू ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती कमला सिन्हा : लेकिन यह स्पेशल मेंशन उठाने वाले बहुत कम सदस्य रह गए हैं, इसलिए पहले उसको ले लिया जाए । इसमें तीन तीन मिनट एक एक सदस्य को समय मिलता है, इसको ले लीजिए । उसके बाद फिर जो सरकार का कार्य है उसको लिया जाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): So, I see that the consensus in the House is that the Copyrigt (Amendment) Bill be disposed of fist. Now, Kumari Selja to move the Bill for consideration.

The Copyright (Amendment) Bill, 1994

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUARI SELJA): Sir, before I move the Bill, I want to make just one clarification. It appears there is a printing mistake in the title of the Copyright (Second Amendment) Bill listed in today's List of Business of the Rajya Sabha against my name, insofar as the word "Second" shown therein is concerned. Therefore, the title of the Bill may kindly be read as "The Copyright (Amendment) Bill, 1994".

Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Copyright Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. There are no amendments.

Clauses 2 to 24 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and Mr. Raj Babar.

KUMARI SELJA: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): I thank all the Members in this House for the excellent cooperation extended to me.

KUMARI SELJA): Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You have to say, thanks with regards. Anyway, let us take up the Special Mentions now.

SPECIAL MENTIONS

Mandrax Tablets

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : आनन्दी बेन पटेल आप क्या बोल रही थीं ।

श्रीमती आनन्दी बेन जेठाभाई पटेल : मैं कह रही थी कि मुझे जल्दी जाना है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): तो फिर उतनी ही जल्दी बोलिए, आपको जितनी जल्दी जाना है ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, everybody wants to go early.

उपसभाध्यक्ष : आपको सदन की अनुमति से मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूं, आप जितनी जल्दी बोलेंगी, उतनी जल्दी हो जाएगा ।

SHRI JAGESH DESAI: I will take my own time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Okay, let me have the list.

श्रीमती आनन्दी जेठाभाई पटेल (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गंभीर और खतरनाक मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।